कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

पौष-माघ 2082, जनवरी 2026

ग्लोबलाईजेशन के गढ़ में

स्वदेशी का आगाज

स्वदेशी मेला

सचित्र झलक

बोकारो, झारखंड

बेंगलूरू, कर्नाटक

प्रयागराज

सीतामढ़ी

स्वदेशी पत्रिका

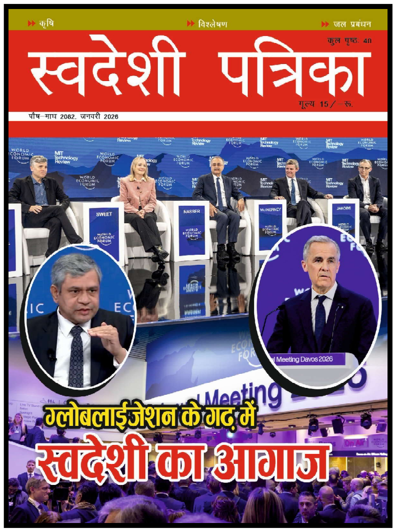

वर्ष–34, अंक–1
पौष–माघ 2082 जनवरी 2026

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–08

ग्लोबलाईजेशन के गढ़ में स्वदेशी का आगाज
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

06 धरोहर
आस्था और सृजन शक्ति का प्रतीक सोमनाथ .... *नरेंद्र मोदी*

10 अंतर्राष्ट्रीय
वेनेजुएला प्रकरण – पेट्रो डालर और बदलती विश्व व्यवस्था .... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

13 कारोबार
मुक्त व्यापार समझौतों में डेयरी और कृषि का बचाव .... *स्वदेशी संवाद*

15 कारोबार
ट्रंप के उग्र टैरिफ के बरक्स – कारगर है घरेलू खपत बढ़ाने की नीति .... *अनिल तिवारी*

17 खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है अरावली का वजूद .... *देविन्दर शर्मा*

19 संस्कृति
'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को समर्पित काशी–तमिल संगमम .... *विनोद जौहरी*

21 लेखा–जोखा
सुदृढ़ आर्थिकी के साथ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश .... *अजय कुमार*

23 पड़ताल
नक्सलवाद का सिमटता दायरा .... *दुलीचंद कालीरमन*

25 आजकल
चर्चा में है चीन और भारत की करीबी .... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

27 मुद्दा
ईरानी बहनें तोड़ रही बुर्का की जंजीरे, भारत में बढ़ रही है कट्टरता .... *संजय सक्सेना*

29 विचार
भारत की संप्रभुता सर्वोपरि – खौफनाक नारेबाजी पर सख्ती जरूरी .... *संध्या जैन*

31 विश्व युवा दिवस
स्वामी विवेकानंद जयंती पर विशेष – क्रांतिकारी विचारों का सन्यासी .... *अनूप पाण्डेय*

33 विश्व युवा दिवस
विवेकानंद एक सशक्त स्त्रीवादी .... *वैदेही*

पाठकनामा

स्वदेशी का पुनर्जन्मः जीआई गौरव बढ़ाता है पोंडुरु बुनकरों की समृद्धि

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु खादी को प्रदान किया गया भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग स्थानीय कारीगरों के लिए परिवर्तनकारी आर्थिक लाभ लाता है, जो उनकी अद्वितीय हस्तनिर्मित सूती कपड़े की रक्षा करता है और आजीविका को बढ़ावा देता है। उत्पाद के मूल और पारंपरिक उत्पादन विधियों – जैसे वलुग मछली की जबड़े से कपास की सफाई और चरखा पर कताई, की कानूनी सुरक्षा करके जीआई सस्ती नकलों को रोकता है, जिससे प्रीमियम मूल्य निर्धारण संभव होता है, जो सीधे कारीगरों की आय में वृद्धि करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की देखरेख में यह मान्यता राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता लक्ष्यों से जुड़ती है, नौकरियां पैदा करती है और प्रामाणिक स्वदेशी उत्पादों की बढ़ी मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जनन प्रदान करती है।

पोंडुरु खादी की जीआई सफलता के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए गांधीजी के आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण पर आधारित बहुआयामी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सरकारें और केवीआईसी जैसे संगठन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आयोजनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जो शहरी उपभोक्ताओं को इसकी श्रेष्ठ गुणवत्ता और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते हैं। ई–कॉमर्स दिग्गजों के साथ जीआई ब्रांडेड बिक्री के लिए सहयोग, साथ ही पोंडुरु साड़ियों पर आधारित फैशन शो, बाजार पहुंच विस्तार करते हुए युवाओं को स्वदेशी शिल्पों के बारे में शिक्षित करते हैं।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक साझेदारियां स्थानीय उत्पादों पर गर्व जगाती हैं, पाठ्यक्रम में स्वदेशी कथाओं को शामिल करती हैं। कारीगर सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन और पोंडुरु गांवों के आसपास पर्यटन सर्किट खरीदारों को आकर्षित करते हैं, आर्थिक विकास को संरक्षण से जोड़ते हैं। मीडिया साझेदारियां सशक्त बुनकरों की कहानियों को बढ़ा–चढ़ाकर बताती हैं, जो उपभोक्ताओं को नैतिक, टिकाऊ खरीदारी की ओर प्रेरित करती हैं। अंततः, जीआई टैगों का उपयोग वैश्वीकरण के बीच स्वदेशी को आधुनिक आंदोलन के रूप में पुनर्जीवित करता है, जिससे कारीगर समृद्ध होते हैं।

विजित कुमार (स्वदेशी कार्यकर्ता), दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और व्यापकता प्रदान करती हैं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विश्व भर में तेजी से विकास हो रहा है। भारत के लिए यह गर्व का क्षण है कि स्टैनफोर्ड एआई सूचकांक में देश को वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन देशों में स्थान दिया है।

अश्वनी वैष्णव, रेलमंत्री, भारत

आज भारत में पारिस्थितिक स्थिरता और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए एक मजबूत और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण है।

भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, भारत

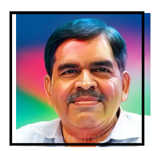

ग्लोबलाइज़ेशन को साफ़ तौर पर नकारा जा रहा है, केवल उन लोगों द्वारा ही नहीं जिन्हें ज़बरदस्ती इसे अपनाने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनके द्वारा भी जिन्होंने पहले इसके एजेंडा को आगे बढ़ाया था।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

10 मिनट के दौर का अंत, गिग वर्कर्स हैं बेहतर बर्ताव के हकदार

13 जनवरी, 2026 को, एक बड़े क्विक कॉमर्स ऐप 'ब्लिंकिट' ने अपने ऐप से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया, और इसी तरह दूसरे खिलाड़ियों ने भी संकेत दिया है कि वे भी अपने–अपने ऐप से 10 मिनट डिलीवरी का ज़िक्र बंद करने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि 10 मिनट डिलीवरी का दौर खत्म हो गया है। क्विक कॉमर्स ई–कॉमर्स का नया रूप है, जो किराने के सामान की फिक्स्ड टाइम ऐप बेस्ड डिलीवरी की तरह है। डार्क स्टोर्स (कस्टमर के सामने न आने वाले वेयरहाउस) के ज़रिए 10–20 मिनट में डिलीवरी का आइडिया मूल रूप से भारत से नहीं आया था। मॉडर्न क्विक–कॉमर्स मॉडल सबसे पहले यूरोप और वेस्ट एशिया में सामने आया। इसके उदाहरण हैं गेटिर (तुर्की), जो 2015 में शुरू हुआ, गोरिल्लाज़ (जर्मनी) जो 2020 में शुरू हुआ, लिंक (जर्मनी), गोपफ (अमरीका) वगैरह। इन कंपनियों ने डार्क स्टोर्स को बहुत तेज़ डिलीवरी के वादे के साथ लोकप्रिय बनाया, जो मुख्य रूप से वेंचर कैपिटल द्वारा वित्त पोषित थी। माना जाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स और प्लेटफॉर्म्स ने 2020–21 के आसपास, खासकर कोविड के दौरान, इन मॉडलों को अपनाया। एक दिलचस्प बात यह थी कि इसे आम तौर पर लोग पसंद करते थे और इस मॉडल ने जल्द ही मार्केट को अपनी ओर खींचा, और शुरुआत में नुकसान के बाद, प्लेयर्स ने इस फॉर्मेट के तहत पैसा कमाना शुरू कर दिया। ई–कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस क्विक कॉमर्स फॉर्मेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मॉडल के तहत, दूसरे देशों में भी कमियां देखी गईं, जहां यह मॉडल पहले शुरू किया गया था। लेकिन भारतीय संदर्भ में, इसकी कड़ी आलोचना हुई है, क्योंकि 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव से डिलीवरी करने वालों पर बहुत दबाव पड़ रहा है, कभी–कभी तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

ई–कॉमर्स के ऐप आधारित सिस्टम के आने के साथ, हम वर्कर्स की एक नई क्लास को उभरते हुए देखते हैं, जिन्हें 'गिग वर्कर्स' कहा जाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि, बहुत सारे बेरोज़गार और अल्प–रोज़गारयुक्त युवा और यहाँ तक कि कुछ अतिरिक्त आमदनी कमाने की चाहत रखने वाले विद्यार्थी भी आसानी से इस काम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है कम मेहनताना देकर वर्कर्स को निचोड़ने का खेल। ऐसा 2023 में हुआ था, जब ई–कॉमर्स कंपनियों ने डिलीवरी एजेंट्स का भुगतान कम कर दिया था, जिससे उनमें गुस्सा फैल गया और वे इसके खिलाफ हड़ताल पर चले गए। हाल ही में, एक बार फिर 'गिग वर्कर्स' अपने काम करने के हालात के खिलाफ थोड़ी देर के लिए हड़ताल पर चले गए, और उनकी एक मांग यह थी कि उन पर दबाव कम करने के लिए 10 मिनट की डिलीवरी खत्म कर दी जाए।

वर्तमान सरकार ने गिग वर्कर्स की परेशानियों पर ध्यान दिया है। भारत सरकार ने श्रम कानूनों में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी है।सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, एग्रीगेटर आदि की स्पष्ट परिभाषा दी गई है।इससे पहले गिग वर्कर्स न तो कर्मचारी माने जाते थे और न ही पूरी तरह स्व–रोज़गार की श्रेणी में आते थे। सरकार का रुख है कि गिग वर्कर्स को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा दी जाए, भले ही वे नियमित कर्मचारी न हों और उन्हें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, मातृत्व लाभ और भविष्य में पेंशन की सुविधा मिले। गिग वर्कर्स को ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है।पंजीकरण के बाद उन्हें यूनिक आईडी और उससे केंद्र व राज्य सरकार की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की योजना पर काम कर रही है।इस कोष में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर का योगदान हो सकता है।

हाल ही में जब मौजूदा केंद्रीय श्रम मंत्री ने प्लेटफॉर्म्स को 10 मिनट की डिलीवरी खत्म करने का सुझाव दिया; और डिलीवरी एजेंट्स की परेशानियों पर ध्यान देते हुए, और ब्लिंकिट ने अपने ऐप से 10 मिनट की डिलीवरी का ऑफर हटा दिया और दूसरे कंपनियों ने भी ऐसा ही बदलाव करने का निर्णय किया है। जहां, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स ने सरकार के 10 मिनट मॉडल में बदलाव करने के सही अनुरोध को मान लिया, वहीं 13 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इटरनल लिमिटेड (ब्लिंकिट की मालिक कंपनी, जो पहले ज़ोमैटो के नाम से जानी जाती थी) से एक अजीब पूछताछ की, जिसमें ब्लिंकिट के "10–मिनट डिलीवरी" वादे को हटाने की खबरों पर सफाई मांगी गई थी, यह सवाल बिजनेस के तरीकों को बेहतर बनाने और उन्हें और इंसानी बनाने में मार्केट की दख़लअंदाजी वाली भूमिका पर एक ज़रूरी सवाल उठाता है। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नहीं पता कि यह तरीका डिलीवरी एजेंट्स के लिए खतरनाक था और इसलिए लोगों की मांग पर कंपनी का यह फैसला एक सही इंसानी काम था।

श्रम का यह नया वर्ग, जिसे गिग वर्कर कहा जाता है, उभरती हुई गिग अर्थव्यवस्था का परिणाम है, जो नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। यह नया वर्ग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों, क्लाउड वर्किंग, रीलांसिंग, ई–कॉमर्स, सप्लाई चेन आदि के रूप में सामने आया है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी और नए व्यावसायिक मॉडल ही इस नए श्रमिक वर्ग के सृजक हैं। ये वर्कर जो ऐप्स से मिले काम/ऑर्डर के आधार पर काम कर रहे हैं, वे साफ़ तौर पर ई–कॉमर्स कंपनियों के ऐप्स के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी परिभाषाओं में, उन्हें वर्कर नहीं माना जाता था, उन्हें 'फ्रीलांसर' कहा जाता रहा। हालांकि सरकार गिग श्रमिकों को सुविधा देने के लिए कई क़दम उठाए हैं। नए श्रम कानूनों में भी उन्हें राहत मिली है। लेकिन आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्लेटफार्म मालिक कंपनियों द्वारा उनके हितों की सुरक्षा करते हुए क़दम उठाए जाएँ।

आस्था और सृजन शक्ति का प्रतीक सोमनाथ

सोमनाथ... यह शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ भारत के आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतीकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का स्थान सबसे पहले होता है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बनता रहा। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। उस दौरान क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है, जिनकी पीड़ा की अनुभूति आज तक होती है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी है। 11 मई, 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति में वह ऐतिहासिक समारोह आयोजित हुआ, जब पुनर्निर्मित मंदिर को दर्शनों के लिए खोला गया।

वर्ष 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार–बार सोमनाथ पर आक्रमण के लिए उकसाने का काम किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था, पर हर बार जब भी मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब

सोमनाथ का प्रतीक यही दर्शाता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।

– नरेंद्र मोदी

हमारे वीरों–वीरांगनाओं ने उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया। सोमनाथ की आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर–दूर तक ले जाते थे।

महमूद गजनवी लूटकर चला गया, मगर सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, विश्वास और प्रबल हुआ। वर्ष 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वह आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हमारी शक्ति का पुंज है। सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है।

हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरा पर जीवन पाया, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे। वहां के अनुभव पर 1897 में चेन्नई में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ' जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार–बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त – जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।

हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरा पर जीवन पाया, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे।

स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने सक्रियता से यह दायित्व संभाला। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण से बहुत उत्साहित नहीं थे और नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी । हालांकि राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख के.एम. मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल' अवश्य पढ़ी जानी चाहिए । पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि हम ऐसी सभ्यता हैं। जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, किंतु उसकी चेतना अमर रही। इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने की शक्ति दी। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प से आज भारत पर विश्व की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। हमारी कला, संस्कृति, संगीत और पर्व–त्योहार आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।

अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ का प्रतीक यही दर्शाता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ। ❑❑

(साभार – दैनिक जागरण, 5 जनवरी 2026)

ग्लोबलाईजेशन के गढ़ में स्वदेशी का आगाज

दशकों से दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के सालाना सम्मेलन में ग्लोबलाईजेशन यानि भूमंडलीकरण के जीत के जश्न का माहौल रहता रहा है। दुनिया भर के सरकारों के प्रमुख जहां इक्कठा होकर तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत्र करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहे हैं, वहीं कारपोरेट जगत के प्रमुखों द्वारा भी यही कहा जाता रहा कि भूमंडलीकरण ही दुनिया के आर्थिक विकास का एकमात्र सही रास्ता है। इन सम्मेलनों में बार–बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि विकासशील देशों सहित सभी देश वांशिगटन मतैक्य के सुझावों को पूरी तरह से लागू करें।

वैश्विक संस्थाएं भी इस विषय पर अपना राग अलापती रही। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र की अलग–अलग संस्थाओं द्वारा लगातार यह तर्क दिया गया कि विकासशील देशों को अपने बाजार, विदेशी सामान, विदेशी सेवाओं और विदेशी पूंजी के लिए पूरी तरह से खोल देने चाहिए। भूमंडलीकरण की शर्तों के हिसाब से बौद्धिक संपदा प्रणाली समेत घरेलू कानूनों में बदलाव हेतु भी निरंतर तर्क दिए जाते रहे। कहा गया कि दुनिया के मूल्य श्रृंखला में हिस्सा लेकर ही विकासशील देश सस्ता सामान बना पाएंगे और तेजी से अपना विकास कर सकेंगे।

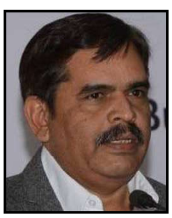

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबलाइज़ेशन को साफ़ तौर पर नकारा जा रहा है, केवल उन लोगों द्वारा ही नहीं जिन्हें ज़बरदस्ती इसे अपनाने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनके द्वारा भी जिन्होंने पहले इसके एजेंडा को आगे बढ़ाया था।

– डॉ. अश्वनी महाजन

लेकिन जनवरी 2026 में हुए दावोस सम्मेलन का माहौल पिछले सम्मेलनों से बिल्कुल अलग दिखा। ग्लोबलाईजशन का जादू जो सिर चढ़कर बोलता था, अब उस पर भरोसा खत्म होता दिखाई दिया। दुनिया के नेता अब भूमंडलीकरण को लेकर सीधे तौर पर शंकाएं व्यक्त करते दिखाई दिए। यहां तक कि भूमंडलीकरण के प्रबल समर्थक भी अब उसके विरोधी खेमे में दिखाई दिए। इस बदलाव में जो आवाज दावोस के गलियारों में जोरदार ढंग से गूंजी, वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की थी। कार्नी ने कहा कि पिछले दो दशकों के गहरे वैश्विक एकीकरण के खराब नतीजे अब साफ दिखाई दे रहे हैं। ये नतीजे वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा और भू–राजनीति के संकट के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक एकीकरण को एक खासियत के रूप में दिखाई जाता था, जो बिना सवाल किए स्वीकार किया जाता था, अब वो कमजोरी का कारण बन गया है।

कार्नी ने आगे कहा कि आज के समय में भूमंडलीकरण के उपकरणों का बड़ी ताकतें हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। टैरिफ, वित्तीय प्रणाली और वैश्विक मूल्य श्रृंखला अब कोई तटस्थ आर्थिक उपकरण नहीं रहे, बल्कि उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब एकीकरण के माध्यम से बड़ी ताकतें दूसरे मुल्कों को अपने अधीन करने का प्रयास कर रही हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि भूमंडलीकरण आपसी फायदे के लिए है।

मार्क कार्नी ने बहुपक्षीय संस्थाओं की कमजोर होती साख पर भी चिंता जताई और कहा कि कनाडा जैसी मध्यम शक्तियों ने विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण सम्मेलनों जैसे संगठनों पर यह भरोसा किया कि ये समस्या समाधान के एक मंच का काम करेंगे, लेकिन आज वो भरोसा संकट में है। अब दुनिया के देश ऊर्जा, फूड यानि खाद्य, वित्त

और जरूरी मिनरल और आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं।

ताकि कोई गलतफहमी न रहे

जब ग्लोबलाईजेशन अपने चरम पर था, तो दुनिया को बार–बार भरोसा दिलाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश उचित और भरोसेमंद नियमों पर आधारित व्यवस्था से चलेंगे। कहा गया कि यह संरचना विवादों को कम करेगी, आर्थिक समायोजन को संभव करेगी और सभी देशों के हितों की रक्षा करेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। व्यवस्था की तटस्थता की गलतफहमी अब टूट चुकी है। कार्नी ने साफतौर पर कहा कि ताकतवर देश अपने देशों के हितों के अनुसार नियमों को सामान्यतौर पर तोड़ते और दरकिनार करते रहे हैं, जबकि उन्हीं नियमों को चुनकर दूसरों पर लागू करते रहे हैं।

इस दोगलेपन के सामने आने के बाद भूमंडलीकरण की असलियत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जो देश खाद्य, ऊर्जा और सुरक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होते, उनके पास बहुत कम रणनीति स्वायतत्ता बचती है। ऐसे हालातों में दूसरों पर निर्भरता चयन नहीं, बल्कि बोझ बन जाती है। इसलिए बड़ी ताकतों की छाया में सुरक्षा पाने की लालसा छोड़ मध्यम शक्तियों को एक दूसरे के सहकार के माध्यम से अपनी ताकत ढूंढ़नी होगी।

गौरतलब है कि आज जब भारत विश्व व्यापार संगठन की संरचना से बाहर कई मुक्त व्यापार समझौते करते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वो इसी सच्चाई को दिखाता है। कनाडा और कई अन्य देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्यम ताकतों के लिए सामुहिक कार्यवाही के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बड़े ताकतवर देशों के दबदबे को संतुलित करने और आर्थिक संप्रभुता को वापिस लाने के लिए जरूरी कदम है।

एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने भूमंडलीकरण के बारे में बांकी दुनिया का नजरिया पेश किया कि कैसे ताकतवर देशों के दबाव में (अमरीका का नाम लिए बिना) वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, वहीं संयुक्त राज्य अमरीका ने इसी दावोस सम्मेलन में खुलकर यह माना कि वैश्वीकरण न केवल अमरीका बल्कि यूरोप में भी असफल हुआ है। अमरीका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लूटनिक ने बिना चीन का नाम लिए अमरीका और यूरोप की चीन पर बढ़ती निर्भरता की ओर भी इशारा किया। लूटनिक ने कहा कि जिस ग्लोबलाईजशन के मॉडल को प्रोत्साहित किया गया था, वो निर्यात करने, मैन्युफैक्चिरिंग को दूसरे देशों की तरफ स्थानांतरित करने और आपूर्ति श्रृंखला को दूरदराज तक ले जाने और दुनिया भर में सबसे सस्ते श्रम की लगातार तलाश पर आधारित था। जबकि इस दृष्टिकोण को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया गया था, उसी ने अमरीका के घरेलू औद्योगिक ढ़ांचे को खोखला कर दिया और अमरीका और इसके श्रमिक पीछे रह गए।

उनका कहना है कि विदेशी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता ने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है, जिससे वे कमज़ोर हो गए हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग आधार कमज़ोर हो गया है। पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विदेश में स्थान्तरित हो गया, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहाँ देश ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बाहरी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर हो गए। उनका कहना है कि यह न तो आर्थिक रूप से टिकाऊ है और न ही रणनीतिक रूप से समझदारीपूर्ण।

इस पृष्ठभूमि में, लुटनिक एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल के तौर पर "अमेरिका फ़र्स्ट" दृष्टिकोण पेश करते दिखाई दिए। यह मॉडल घरेलू कामगारों और राष्ट्रीय औद्योगिक क्षमता को आर्थिक नीति के केंद्र में रखता है। वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी देश को अपने पूरे औद्योगिक ढांचे को विदेश में स्थानांतरित नहीं कर देना चाहिए या कुशलता अथवा कम लागत के नाम पर खुद को खोखला नहीं होने देना चाहिए। उनके हिसाब से, आर्थिक मज़बूती के लिए मुख्य उत्पादन क्षमताओं को राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर बनाए रखना ज़रूरी है।

लुटनिक आगे सुझाव देते हैं कि यह दृष्टिकोण सिर्फ़ संयुक्त राज्य अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। वह दूसरे देशों को अपने विकास के रास्तों पर सोचने और ऐसे मॉडल पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आत्मनिर्भरता, घरेलू रोज़गार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कम निर्भरता को प्राथमिकता देते हैं। असल में, वह अंधे ग्लोबलाइज़ेशन से हटकर एक ज़्यादा संतुलित आर्थिक ढांचे की ओर जाने की बात करते हैं जो देश के हितों और मज़दूरों की सुरक्षा करे।

दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबलाइज़ेशन को साफ़ तौर पर नकारा जा रहा है। केवल उन लोगों द्वारा ही नहीं जिन्हें ज़बरदस्ती इसे अपनाने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनके द्वारा भी जिन्होंने पहले इसके एजेंडा को आगे बढ़ाया था। आत्मनिर्भरता, ग्लोबल वैल्यू चेन पर निर्भरता को नकारने, 'नेशन फर्स्ट' दृष्टिकोण की आवाज़ें खुले तौर पर उठाई गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान करेंसी, भुगतान व्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला को हथियार बनाने का मुद्दा खुले तौर पर उठाया गया है। इसके लिए आत्मनिर्भरता, बाकी दुनिया पर निर्भरता छोड़ने, और बड़ी ताकतों द्वारा शोषण से बचने के तर्कों की गूँज भूमंडलीकरण के गढ़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, में स्वदेशी के आग़ाज़ की खुली घोषणा जैसी है। ❑❑

वेनेजुएला प्रकरण

पेट्रो डालर और बदलती विश्व व्यवस्था

वेनेजुएला आज जब वैश्विक राजनीति के मंच पर एक संकटग्रस्त देश के रूप में दिखाई देता है, तो बहुत कम लोग यह स्मरण करते हैं कि इसकी कहानी वास्तव में सौ वर्ष पहले ही लिखी जाने लगी थी। बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में, जब विश्व औद्योगिक सभ्यता की ऊर्जा आवश्यकताओं से जूझ रहा था, तब वेनेजुएला की धरती के नीचे छिपे विशाल तेल भंडारों पर पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सबसे पहले नजर पड़ी थी। स्टैंडर्ड ऑयल, रॉयल डच शेल और बाद में एक्सॉन, गल्फ ऑयल तथा शेवरॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों ने लेक माराकाइबो और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेल उत्खनन का विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे तेल पर निर्भर होती चली गई, लेकिन उस तेल से पैदा होने वाला वास्तविक लाभ देश के भीतर नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन और ह्यूस्टन के कॉरपोरेट मुख्यालयों में जाता रहा।

यह स्थिति औपनिवेशिक युग की एक नई शक्ल थी – जहाँ झंडे और सेनाएँ नहीं थीं, लेकिन संसाधनों पर नियंत्रण था। राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद आर्थिक संप्रभुता सीमित थी। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने 1976 में वेनेजुएला को एक ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। पहली जनवरी 1976 को सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और पीडीवीएसए नामक राष्ट्रीय तेल कंपनी की स्थापना की। यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक घोषणा थी कि अब वेनेजुएला अपनी धरती के नीचे छिपे संसाधनों का स्वामी स्वयं होगा।

अब उपनिवेशवाद का अर्थ बदल चुका है। अब भूमि पर कब्जा नहीं, बल्कि प्रणाली पर नियंत्रण होता है। अब साम्राज्य नक्शे पर नहीं, बल्कि मुद्राओं, बैंकों और ऊर्जा मार्गों में बसते हैं। और इसीलिए, इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा संघर्ष युद्ध का नहीं, स्वदेशी चेतना का संघर्ष है।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

लेकिन इस राष्ट्रीयकरण को सही अर्थों में समझने के लिए हमें उस दौर की वैश्विक व्यवस्था को देखना होगा। 1971 में अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली से बाहर निकलकर डॉलर को सोने से अलग कर दिया था। इससे डॉलर की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा,

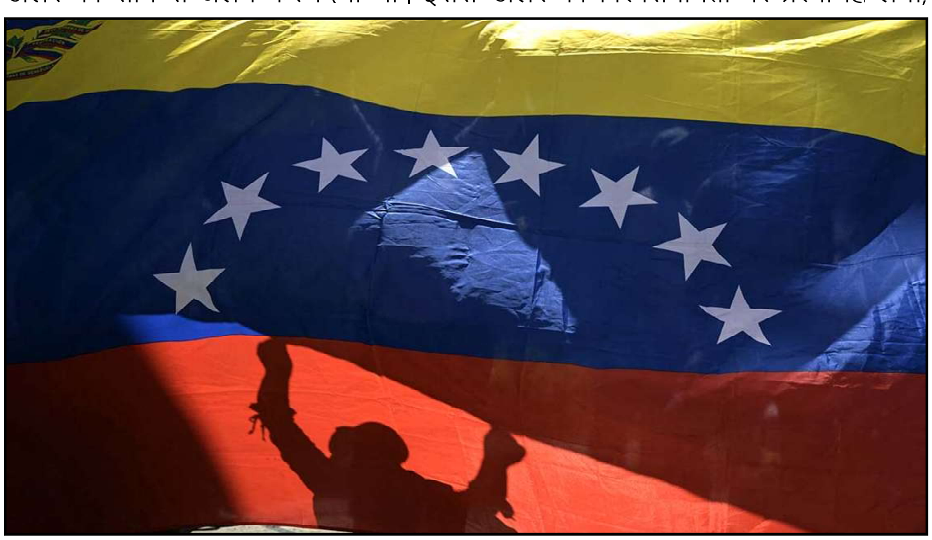

किंतु बहुत शीघ्र अमेरिका ने इसका एक नया समाधान खोज लिया – पेट्रोडॉलर प्रणाली। इसके अंतर्गत तेल का वैश्विक व्यापार लगभग पूरी तरह अमेरिकी डॉलर में होने लगा। जो भी देश तेल खरीदना चाहता था, उसे डॉलर रखना पड़ता था। और जो देश तेल बेचता था, वह अपना अधिशेष डॉलर अमेरिकी बैंकों और ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करता था। इस प्रकार तेल, डॉलर और अमेरिकी वित्तीय शक्ति एक अदृश्य त्रिकोण में बंध गए।

यहीं से आधुनिक वैश्विक सत्ता की असली संरचना बनती है – जहाँ सेना से अधिक महत्वपूर्ण मुद्रा होती है, और मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण संसाधन। वेनेजुएला इसी प्रणाली का हिस्सा था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद तेल अब केवल निर्यात वस्तु नहीं रहा – वह राजनीतिक शक्ति का साधन बन गया।

यह प्रवृत्ति विशेष रूप से तब स्पष्ट हुई, जब 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। चावेज केवल समाजवादी नेता नहीं थे, बल्कि वे उस वैश्विक व्यवस्था के आलोचक थे जिसमें विकासशील देशों को केवल कच्चा माल देने वाला माना जाता था। उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका की नीतियों को चुनौती दी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से दूरी बनाई, और "दक्षिण–दक्षिण सहयोग" की बात की। चावेज का सपना था कि लैटिन अमेरिका केवल बाजार नहीं, बल्कि सभ्यताओं का स्वायत्त क्षेत्र बने।

चावेज के बाद निकोलस मादुरो के शासन में यह दिशा और स्पष्ट हो गई। इसी दौरान चीन वेनेजुएला के परिदृश्य में एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरा। चीन ने वेनेजुएला को बड़े पैमाने पर ऋण दिए, बुनियादी ढांचे में निवेश किया और बदले में दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौते किए। यह संबंध पश्चिमी शैली के निवेश से भिन्न था – इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार या शासन सुधार की शर्तें नहीं थीं। यह विशुद्ध रणनीतिक साझेदारी थी।

धीरे-धीरे वेनेजुएला ने डालर आधारित व्यवस्था से बाहर निकलने के छोटे-छोटे प्रयोग शुरू किए। कुछ तेल सौदे गैर-डालर माध्यमों से हुए, कुछ वस्तु-विनिमय के रूप में, और कुछ तथाकथित ''छाया जहाजों'' के माध्यम से। ये कदम वैश्विक स्तर पर छोटे थे, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था।

धीरे–धीरे वेनेजुएला ने डॉलर आधारित व्यवस्था से बाहर निकलने के छोटे–छोटे प्रयोग शुरू किए। कुछ तेल सौदे गैर–डॉलर माध्यमों से हुए, कुछ वस्तु–विनिमय के रूप में, और कुछ तथाकथित "छाया जहाजों" के माध्यम से। ये कदम वैश्विक स्तर पर छोटे थे, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। यह संकेत था कि दुनिया अब एकमात्र मुद्रा व्यवस्था को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है।

यहीं से अमेरिका की चिंता वास्तविक रूप लेती है। क्योंकि पेट्रोडॉलर व्यवस्था केवल आर्थिक प्रणाली नहीं है, वह अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व की रीढ़ है। अमेरिका की शक्ति का आधार उसका उत्पादन नहीं, बल्कि उसकी मुद्रा है। वह डॉलर छापकर पूरी दुनिया से वास्तविक संसाधन खरीदता है। जैसे ही कोई बड़ा तेल उत्पादक देश डॉलर से बाहर व्यापार करता है, यह पूरी संरचना हिलने लगती है।

अमेरिका की प्रतिक्रिया कूटनीतिक नहीं, बल्कि वित्तीय और रणनीतिक होती है। वेनेजुएला पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसकी तेल कंपनी, केंद्रीय बैंक, जहाजरानी नेटवर्क और अनेक अधिकारियों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से काट दिया जाता है।

इन प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, महँगाई नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और करोड़ों लोग देश छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने लगते हैं। अपराध, तस्करी और अवैध व्यापार बढ़ता है। आर्थिक संकट धीरे–धीरे मानवीय संकट में बदल जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम को केवल वेनेजुएला की विफलता के रूप में देखना ऐतिहासिक भूल होगी। वास्तव में यह उस नई वैश्विक व्यवस्था की अभिव्यक्ति है जिसमें प्रतिबंध, मुद्रा नियंत्रण और संसाधनों पर कब्जा – नए उपनिवेशवाद के औजार बन चुके हैं।

इसी परिवर्तनशील वैश्विक चेतना का एक अत्यंत प्रतीकात्मक दृश्य 2026 के दावोस सम्मेलन में दिखाई देता है। विश्व आर्थिक मंच, जो कभी वैश्विक पूँजीवाद और मुक्त बाजार का उत्सव हुआ करता था, अब स्वयं आत्ममंथन का मंच बन चुका है। दावोस में अमेरिका और यूरोप के नीति–निर्माताओं, कॉरपोरेट प्रमुखों और अर्थशास्त्रियों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह "नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था", जिसके सहारे पश्चिमी दुनिया ने दशकों तक वैश्विक नेतृत्व किया, अब व्यवहार में काम नहीं कर रही है। डॉलर की स्थिरता पर प्रश्न उठ रहे हैं, मुक्त व्यापार की जगह संरक्षणवाद ले रहा है, वैश्वीकरण का स्थान "रणनीतिक क्षेत्रीयकरण" ले रहा है, और संस्थागत बहुपक्षीयता धीरे–धीरे शक्ति संतुलन की राजनीति में बदल रही है।

इसी मंच पर अमेरिकी नेतृत्व द्वारा एक नए "शांति मंच" – तथाकथित शांति बोर्ड (बोर्ड आफ पीस) का प्रस्ताव भी सामने आता है, जिसे वैश्विक संघर्षों के

आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लगभग ३०० अरब बैरल से अधिक। यह सऊदी अरब से भी अधिक है। अंतर केवल इतना है कि सऊदी अरब पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के भीतर रहकर तेल बेचता है, जबकि वेनेजुएला उस व्यवस्था से बाहर निकलने का साहस करता है।

समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु यह मंच न तो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि से बंधा है, न उसके पास कोई वैधानिक अधिकार है, न आर्थिक या सैन्य बाध्यकारी शक्ति। वह संयुक्त राष्ट्र का विकल्प नहीं, बल्कि उसके खोखलेपन की स्वीकारोक्ति है। यह शांति की संस्था नहीं, बल्कि शांति की भाषा में सत्ता को वैध ठहराने का एक नया उपकरण है। जब वही शक्ति जो प्रतिबंध लगाती है, टैंकर जब्त करती है और सैन्य हस्तक्षेप करती है, स्वयं "शांति मंच" की घोषणा करे – तो यह शांति नहीं, बल्कि नए युग की शक्ति–कूटनीति का नाट्य मंच बन जाता है।

इसी परिवेश में 3 जनवरी 2026 को अमेरिका वेनेजुएला में प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई करता है। राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया जाता है, तेल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और अमेरिकी नौसेना कई तेल टैंकरों को अपने अधिकार में ले लेती है। इसे अमेरिका सुरक्षा अभियान कहता है, लेकिन विश्व का बड़ा हिस्सा इसे आर्थिक प्रभुत्व की खुली घोषणा के रूप में देखता है।

यह आधुनिक युग का मुनरो सिद्धांत है – फर्क सिर्फ इतना है कि अब लक्ष्य भू–भाग नहीं, बल्कि ऊर्जा और मुद्रा है।

आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लगभग 300 अरब बैरल से अधिक। यह सऊदी अरब से भी अधिक है। अंतर केवल इतना है कि सऊदी अरब पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के भीतर रहकर तेल बेचता है, जबकि वेनेजुएला उस व्यवस्था से बाहर निकलने का साहस करता है। यही साहस उसे संकट का केंद्र बनाता है।

यहाँ चीन और अमेरिका का द्वंद स्पष्ट हो जाता है। चीन को अपने औद्योगिक भविष्य के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, और अमेरिका को अपने वित्तीय प्रभुत्व के लिए पेट्रोडॉलर व्यवस्था को बचाए रखना है। वेनेजुएला इन दोनों के बीच खड़ा वह द्वार है, जिस पर नियंत्रण से वैश्विक संतुलन की दिशा बदल सकती है।

अमेरिका की वर्तमान आक्रामकता के पीछे एक गहरी आर्थिक असुरक्षा छिपी हुई है। भारी सार्वजनिक ऋण, लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा, उत्पादन की तुलना में उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, और डॉलर पर बढ़ता वैश्विक अविश्वास – ये सब मिलकर अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहाँ उसकी शक्ति का आधार अब वास्तविक उत्पादन नहीं, बल्कि वित्तीय प्रभुत्व और सैन्य दबाव बन चुका है।

सरल शब्दों में कहें तो, अमेरिका अपनी आंतरिक आर्थिक कमजोरी का इलाज बाहरी दुनिया पर नियंत्रण बढ़ाकर करने की कोशिश कर रहा है।

आज का विश्व बहुध्रुवीय है। जिसमें चीन औद्योगिक शक्ति है, रूस रणनीतिक शक्ति है, यूरोप नियामक शक्ति है, और भारत सभ्यतागत शक्ति है। इस नई व्यवस्था में कोई एक केंद्र नहीं, बल्कि कई प्रतिस्पर्धी केंद्र हैं।

इसी बिंदु पर भारत की भूमिका केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और सभ्यतागत हो जाती है। भारत की परंपरा हमें स्वदेशी का सिद्धांत देती है, अर्थात् आर्थिक विकास का वह मॉडल जो स्थानीय संसाधनों, स्थानीय श्रम और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हो, न कि वैश्विक कॉरपोरेट नियंत्रण पर।

और भारत हमें एकात्म मानववाद का दर्शन देता है – जो मनुष्य, समाज, प्रकृति और अर्थव्यवस्था को अलग–अलग इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही जीवंत तंत्र के रूप में देखता है। एकात्म मानववाद के अनुसार विकास का लक्ष्य केवल जीडीपी नहीं, बल्कि मनुष्य की संपूर्ण उन्नति है – भौतिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था मनुष्य को उपभोक्ता मानती है, प्रकृति को संसाधन, और राष्ट्रों को बाजार। इसके विपरीत, एकात्म मानववाद मनुष्य को चेतन सत्ता, प्रकृति को सहचर, और राष्ट्रों को सभ्यतागत इकाइयाँ मानता है। यही आर्थिक उपनिवेशवाद का वास्तविक विकल्प है।

वेनेजुएला की गाथा केवल एक देश की त्रासदी नहीं है। यह पूरी मानवता के सामने रखा गया प्रश्न है।

क्या दुनिया फिर से साम्राज्यों के अधीन चलेगी, या सभ्यताओं के संवाद से एक नई व्यवस्था गढ़ेगी?

अब उपनिवेशवाद का अर्थ बदल चुका है। अब भूमि पर कब्जा नहीं, बल्कि प्रणाली पर नियंत्रण होता है। अब साम्राज्य नक्शे पर नहीं, बल्कि मुद्राओं, बैंकों और ऊर्जा मार्गों में बसते हैं। और इसीलिए, इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा संघर्ष युद्ध का नहीं, स्वदेशी चेतना का संघर्ष है। ❑❑

मुक्त व्यापार समझौतों में डेयरी और कृषि का बचाव

कुछ दिन पहले भारत ने न्यूज़ीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों के साथ भी एफटीए कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कुछ हैरानी से देखा जा रहा है जबकि नवंबर 2019 में भारत ने स्वयं को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) से बाहर कर लिया था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दोनों शामिल थे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ अलग–अलग एफटीए कैसे कर लिए?

आरसीईपी एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता था, जिसमें मुक्त व्यापार से जुड़े प्रावधान शामिल थे। इसमें 16 देश–10 आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत भागीदार थे। इस समझौते पर लगभग आठ वर्षों तक बातचीत चली। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत ने आरसीईपी से बाहर निकलने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि समझौते का अंतिम प्रारूप भारत की अपेक्षाओं और हितों के अनुरूप नहीं था।

4 नवंबर 2019 को आरसीईपी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने उन्हें इस समझौते से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया।

अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को अंतिम क्षण में इस समझौते से पीछे हटने का साहसिक कदम कैसे लिया? संभवतः यह विश्व इतिहास में पहली बार था जब किसी सरकार के मुखिया ने वर्षों की बातचीत और अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद भी, शिखर सम्मेलन में अन्य सभी नेताओं के सामने यह घोषणा की कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। वास्तव में, डेयरी और कृषि ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र थे, जिन पर भारत ने कठोर रुख अपनाया। न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मांग थी कि आरसीईपी के सदस्य देश अपने डेयरी और कृषि बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलें।

यदि अमेरिका भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए एफटीए से संकेत ले और अपनी मांगों को यथार्थवादी स्तर तक सीमित करे, तो भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में आ रही बाधाओं का समाधान निकालना कठिन नहीं होगा।

– स्वदेशी संवाद

आरसीईपी से भारत के बाहर निकलने और बाद में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के साथ अलग–अलग मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने के बीच जो विरोधाभास दिखाई देता है, उसे समझने के लिए आरसीईपी की संरचना को समझना आवश्यक है। आरसीईपी में जो 16 देश शामिल थे, इनमें से 10 आसियान देशों के साथ भारत के पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते मौजूद थे। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी भारत के एफटीए पहले से लागू थे। वहीं, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की द्विपक्षीय एफटीए वार्ताएँ अलग–अलग चल रही थीं। इस परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही ऐसा देश बचता था, जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए गंभीर जोखिम माना जा रहा था और वह देश था चीन। इसलिए भारत ने आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया और इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के साथ अलग–अलग, द्विपक्षीय समझौते करने का रास्ता चुना।

जब भारत ने अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए, तो कई लोगों को हैरानी हुई कि कृषि और डेयरी को बाहर रखते हुए यह समझौता कैसे किया गया। हालांकि, इस कदम की व्यापक सराहना भी हुई। अब जब न्यूज़ीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता

किया गया है और उसमें भी कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, तो यह दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट हो जाता है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय अत्यंत सतर्क रहा है और उसने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और डेयरी, को बाहर रखने में सफलता हासिल की है।

अब प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसे देश के लिए कृषि और डेयरी की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यदि कृषि और डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल किया जाए, तो इससे भारतीय कृषि और डेयरी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उनका यह भी कहना है कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

आजीविका और खाद्य सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों से आता है, जिनके पास औसतन केवल एक या दो दुधारू पशु होते हैं। इनके लिए दूध केवल अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन का आधार है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है और 8 करोड़ से अधिक परिवार यानि 36 करोड़ लोग डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं।

इसके विपरीत, अमेरिका और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में डेयरी एक व्यापार–केंद्रित उद्योग है, जहाँ उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः निर्यात और मुनाफ़ा होता है, न कि व्यापक ग्रामीण आजीविका। निस्संदेह, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। मात्रा की दृष्टि से देखें, तो लीटर में दुग्ध उत्पादन कई प्रमुख कृषि फसलों के किलोग्राम में उत्पादन से भी अधिक है। भारत में अधिक दूध उत्पादन के पीछे प्रमुख कारण यह है कि देश में दुग्ध उत्पादों–विशेषकर दूध के दाम अपेक्षाकृत लाभकारी हैं, जिससे छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

यह भी सर्वविदित है कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दुग्ध उत्पादों, विशेषकर मिल्क पाउडर, की कीमतों में भारी अंतर है। यदि न्यूज़ीलैंड का दूध या दूध पाउडर बिना शुल्क (टैरिफ) के भारत में आने लगे, तो घरेलू बाजार में कीमतों में तेज़ गिरावट आएगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि देश के लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बने रहने का दर्जा खो देगा, बल्कि यहाँ एक गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह कृषि उत्पाद हो या दूध, भारत जैसे विशाल देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है।

अमेरिका के साथ समझौता और कृषि

ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ़ के बाद भारत और अमेरिका, दोनों ही, एक व्यापक व्यापार समझौते पर पहुँचने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा कृषि क्षेत्र बनकर उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ब्राज़ील के बाद, सोयाबीन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रंप टैरिफ़ के बाद चीन, जो अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था, ने अमेरिका से आयात में भारी कटौती कर दी है। इसी तरह अमेरिका अन्य कृषि उत्पादों का भी अधिशेष उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए वह नए विदेशी बाज़ार तलाश रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारतीय बाज़ार में अपने कृषि उत्पादों के लिए आक्रामक रूप से प्रवेश चाहता है, जबकि भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है। भारत के इस विरोध के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं।

पहला, यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाज़ार में प्रवेश की अनुमति देता है, जो अमेरिकी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी से समर्थित हैं, तो भारतीय किसान इस असमान प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे और उत्पादन बंद करने को मजबूर हो सकते हैं। इससे आजीविका का नुकसान, बेरोज़गारी में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में गिरावट आएगी, जो भारत को खाद्य असुरक्षा की ओर भी धकेल सकती है।

दूसरा, अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोलने से भारत की जैव–सुरक्षा और बीज संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के अधिकांश कृषि उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) होते हैं और पेटेंट के अधीन होते हैं। भारत ने लंबे समय से जीएम खाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रुख अपनाया है। मज़बूत घरेलू नियंत्रणों के बिना जीएम फसलों को अपनाने से किसानों की लागत बढ़ सकती है, बीजों पर निर्भरता गहरी हो सकती है और ऐसे पारिस्थितिक जोखिम पैदा हो सकते हैं, जिनकी भरपाई बाद में संभव नहीं होगी। इसलिए किसी भी अमेरिकी व्यापार समझौते के दबाव में जल्दबाज़ी करने के बजाय, भारत के लिए वैज्ञानिक विवेक और स्वदेशी अनुसंधान को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि अमेरिका भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए एफटीए से संकेत ले और अपनी मांगों को यथार्थवादी स्तर तक सीमित करे, तो भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में आ रही बाधाओं का समाधान निकालना कठिन नहीं होगा। ❑❑

(साभारः दैनिक आज)

ट्रंप के उग्र टैरिफ के बरक्स

कारगर है घरेलू खपत बढ़ाने की नीति

इस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए जा रहे शुल्क के डर से दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका के सामने झुक कर उसकी व्यापार शर्तों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भारत अमेरिका के साथ कारोबार समझौते के तहत अपने करोड़ों किसानों और मछुआरों के हितों के मद्देनजर बिना झुके अपनी शर्तों के साथ अडिग है। ऐसे में पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत अमेरिका के ऊंचे शुल्क का अपनी मजबूत घरेलू खपत के हथियार से मुकाबला कर रहा है। बीते पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधार की घोषणा की थी। उसके बाद से क्रियान्वयन की दिशा में लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है। उम्मीद के अनुरूप इससे भारत में घरेलू खपत तेजी से बढ़ रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए पचास फीसद शुल्क से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर प्रकाशित वैश्विक रपटों में कहा जा रहा है कि भारत की घरेलू खपत मजबूत है। ऐसे में भारत की विकास दर में किसी चिंताजनक गिरावट की आशंका नहीं है। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजंसी 'एसएंडपी' ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसद ऊंचे शुल्क लगाने से उसकी आर्थिक तरक्की पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। भारत की 'सावरेन रेटिंग' का नजरिया अभी भी सकारात्मक बना रहेगा। चूंकि भारत एक निर्यात–उन्मुख अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसे में उसे फिलहाल शुल्क संबंधी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 'एसएंडपी' का मानना है कि भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025–26 में 6.5 फीसद रहेगी। इसी तरह 'मार्गन स्टेनली रिसर्च' के एक विश्लेषण में भी भारत की घरेलू मांग मजबूत होने की बात कही गई है।

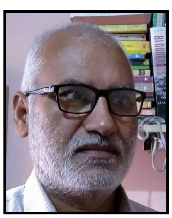

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए अब नीतिगत समर्थन बढ़ाना जरूरी होगा। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योग–कारोबार को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना जरूरी होगा।

–अनिल तिवारी

इस समय भारत की विकास दर को मजबूत आंतरिक घरेलू आधार मिला हुआ है। अब इसे लगातार आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की विकास दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से दोगुना से भी अधिक रहने का अनुमान है। इसी तरह रेटिंग एजंसी 'क्रिसिल' ने अपनी रपट में कहा है कि भारत में घरेलू खपत में सुधार, भरपूर खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, सस्ते कर्ज और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक संकेतों के कारण इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत की विकास दर 6.4 फीसद के स्तर से ऊपर की ही होगी।

पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लोकसभा में कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल केंद्र मानती हैं। अमेरिका ने जो शुल्क लगाए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों, निर्यातकों और उद्योगों के हितों की रक्षा

करेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के लिए वित्तीय, श्रम और कृषि सुधारों को लागू करने की डगर पर बढ़ना अब जरूरी है।

इस बीच खाद्य पदार्थ और कारखाने में बनी चीजों के दाम बढ़ने से हालिया दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर अपने 8 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित होलसेल इन्फ्लेशन साल भर पहले के मुकाबले 0.83 प्रतिशत रही जबकि दिसंबर 2024 में यह 2.75 प्रतिशत थी। दिसंबर में थोक महंगाई दर 2 महीना के बाद शून्य से ऊपर आई है। अक्टूबर में यह माइनस 1.02 प्रतिशत और नवंबर में माइनस 0.32 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर में महंगाई का पॉजिटिव रेट मुख्य रूप से मिनरल्स, मशीनरी टेक्सटाइल और कारखाने में बने फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के चलते रहा है। लेकिन देश के कई नामचीन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कुल मिलाकर होलसेल इन्फ्लेशन अभी भी सुगम स्तर पर बना हुआ है। खेती किसानी की बेहतर स्थिति, जलाशयों में पानी के अच्छे स्तर को देखते हुए आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों का दबाव निश्चित रूप से धीरे–धीरे कम होता हुआ दिखेगा। दिसंबर में खाद्य पदार्थों में महंगाई दर बढ़कर –0.43 प्रतिशत हो गई जो कि नवंबर में –4.5 प्रतिशत थी। अनाज, दाल और सब्जियों के थोक भाव नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बढ़कर खाने में बनी चीजों में थोक महंगाई दर 1.82 प्रतिशत हो गई जो नवंबर में 1.33 प्रतिशत थी। नान फुट कैटेगरी में महंगाई दर 2.95 प्रतिशत रही जो नवंबर में 2.27 प्रतिशत थी। समय–समय पर थोड़े बहुत उतार–चढ़ाव के बावजूद इस वित्त वर्ष में महंगाई दर 0.4 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना बताई जा रही है।

हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर बढ़ाने के बावजूद घरेलू बाजार में खपत को बढ़ावा मिल रहा है। सस्ते कर्ज से उद्योग–कारोबार में उत्साह है। कृषि क्षेत्र में रेकार्ड उत्पादन, मानसून की अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर और मजबूत खरीफ बुवाई से सकारात्मक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, नवउद्यम, नवोन्मेष, तेजी से बढ़ता बाजार और सेवा क्षेत्र की ऊंचाइयां ऐसी शक्तियां हैं, जो दुनिया के देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआइ ने घटाया है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमान 3.7 फीसद से घटा कर 3.1 फीसद कर दिया है। जून 2025 में खुदरा महंगाई घट कर 2.1 फीसद पर आ गई। मई में खुदरा महंगाई दर 2.82 फीसद रही। इतना ही नहीं, जून में थोक महंगाई दर भी 20 महीने में पहली बार ऋणात्मक हुई। यह घट कर –0.13 फीसद रह गई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में गिरावट के साथ–साथ विनिर्मित उत्पादों की लागत में भी कमी आई। मई में थोक महंगाई दर 0.39 फीसद थी। जहां महंगाई में तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभप्रद है, वहीं भारत में सस्ते कर्ज से भी घरेलू उपचार में खपत और आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी।

विगत दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50 फीसद की कटौती का एलान किया। अब रेपो रेट छह फीसद से घट कर 5.5 फीसद हो गई है। इस वर्ष 2025 में फरवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक फीसद की बड़ी कटौती करते हुए इसे तीन फीसद पर ला दिया है।

निश्चित रूप से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते अहम हैं। भारत को संयुक्त अरब और आस्ट्रेलिया के साथ समझौते से लाभ हुआ है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर हुए।

भारत का स्विटजरलैंड और चार सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता अक्तूबर 2025 से लागू हो चुका है। इन सबके साथ–साथ भारत–आसियान के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चर्चा जारी है। आसियान में ब्रुनोई, कांबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए अब नीतिगत समर्थन बढ़ाना जरूरी होगा। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योग–कारोबार को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना जरूरी होगा। उम्मीद करें कि सरकार घरेलू खपत के इजाफे के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यह भी उम्मीद है कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए पचास फीसद शुल्क की चुनौती से मुकाबला करने के लिए घरेलू बाजार की खपत को हर संभव तरीके से और मजबूत बनाते हुए विकास दर को ऊंचाई पर बनाए रखेगी। ❑❑

खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है अरावली का वजूद

वर्ष 2021 की हॉलीवुड व्यंग्य फिल्म 'डोंट लुक अप' में, दो अमेरिकी खगोलशास्त्री दुनिया को एक धूमकेतु के बारे में चेतावनी देते हैं, जो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति एक अरबपति के झांसे में आ जाते हैं, जो यह दावा करता है कि उस आकाशीय पिंड में खरबों डॉलर के दुर्लभ तत्व हैं। आखिरकार, धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है, जिससे एक वैश्विक आपदा बनती है।

काश! फिल्म के मुख्य किरदारों ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के भयानक परिणामों के बारे में संज्ञान लिया होता, जैसा कि उत्तर भारत के 'हरे फेफड़े' पुकारी जाने वाली और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील किंतु क्षतिग्रस्त की जा चुकी अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रस्तावित 100 मीटर की परिभाषा से साफ था तो फिल्म का शीर्षक 'डोंट लुक अप, लुक डाउन' होता। यह वही है, जिसकी चेतावनी महात्मा गांधी ने यह कहकर दी थी, 'दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं।'

कई साल पहले, मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर जलाशय के ऊपर हिमालय की नाजुक पहाड़ियों में चूना पत्थर की खुदाई पर रिपोर्टिंग करने गया था। एक सीमेंट कंपनी धीरे–धीरे, परत–दर–परत, चूना पत्थर वाली पहाड़ी को खुरच रही थी। जब मैंने कंपनी के महाप्रबंधक से पूछा कि क्या उन्हें अहसास है कि पहाड़ी को समतल करने से गंभीर पारिस्थितिक नुकसान होगा, तो उनके जवाब में आमतौर पर हावी मानसिकता झलक रही थी, 'जब पहाड़ी ही नहीं रहेगी तो आप किस पारिस्थितिक नुकसान की बात कर रहे हैं?'

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित सभी विकास गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मुख्य आवश्यक तत्वों के अत्यधिक खनन के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं और इसके लिए सख्त

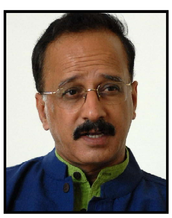

एक अरब साल से भी ज्यादा पुरानी अरावली पहाड़ियों ने उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान बनने के विरुद्ध एक हरी दीवार का काम किया है। ये पहाड़ियां समृद्ध जैव विविधता का भंडार भी हैं।

– देविन्दर शर्मा

नियमों के अलावा प्रकृति द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन की भी जरूरत है। इसके सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, जिनके लिए कोई माप–सूत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में, अगर नीति निर्माताओं को गलती करनी भी पड़े, तो उन्हें लोगों और पर्यावरण के हित में गलती करनी चाहिए। इसी तरह, जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगे, तब एक ऐसा कथानक गढ़ने की कोशिश की गई जो उन दावों को चुनौती दे रहा था, जिसमें इस घटनाक्रम को जलवायु आपदा बताया गया था। भगवान का शुक्र है कि अब दुनिया पिघलते ग्लेशियरों के विनाशकारी परिणामों के प्रति जाग गई है। ग्लोबल वार्मिंग से आगे बढ़कर, दुनिया पहले ही ग्लोबल बॉइलिंग स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब है पहाड़ियों और जंगलों का अंधाधुंध दोहन, जो दुनिया को सिर्फ जलवायु आपदा की ओर धकेलेगा।

चार राज्यों–गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में 1. 44 लाख वर्ग किमी में फैली अरावली पहाड़ियों में सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा और बेशक, संगमरमर जैसे मुख्य खनिजों का भरपूर भंडार है। इसके अलावा, ये पहाड़ियां लिथियम, निकेल, मोलिब्डेनम, नाइओबियम और टिन जैसे जरूरी खनिजों से भी भरपूर हैं। जैसे 'डोंट लुक अप' में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया गया था कि धूमकेतु की आर्थिक संपत्ति बहुत ज्यादा दौलत लाएगी, वैसे ही यह माना जा रहा है कि अरावली में मौजूद खनिज देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। अगर ऐसा है, तो मुझे नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर 'सेव अरावली' विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। क्या लोग खनिज संपदा की आर्थिक कीमत नहीं समझते, जिसे किसी भी कीमत पर निकालना जरूरी है?

एक अरब साल से भी ज्यादा पुरानी अरावली पहाड़ियों ने उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र

निःसंदेह, अरावली की पहाड़ियां महज रणनीतिक खनिजों के लिए एक प्राकृतिक भंडार नहीं हैं, वे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करती हैं। प्रकृति प्रदत्त इन पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सेवाओं की वास्तविक आर्थिक लागत का पता नहीं लगाया गया है।

के रेगिस्तान बनने के विरुद्ध एक हरी दीवार का काम किया है। ये पहाड़ियां समृद्ध जैव विविधता का भंडार भी हैं। ये जमीन के नीचे के जलभंडारों की भरपाई करने में अहम भूमिका निभाती हैं और इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेगिस्तान की आगे बढ़ने की चाल को रोका है। लेकिन अरावली पट्टी में इंसानी दखल और विकास प्रक्रिया के कारण वन्यजीवों के आवासों और स्थानीय आजीविका को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। जैसे–जैसे रेगिस्तान फैल रहा है, देश की कड़ी मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

फरवरी, 2025 में संसद को बताया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए 2021 के भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानचित्र के अनुसार, रेगिस्तान तेजी से अन्न पैदा करने वाली कृषि भूमि की ओर बढ़ रहा है। पहले से ही, हरियाणा में 3.64 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, पंजाब में 1.68 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 1.54 लाख हेक्टेयर भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुकी है। एक बार अरावली का स्वरूप नई परिभाषा के अनुसार बन गया तो भूमि क्षरण और भी तेज हो जाएगा। इससे तेज गर्म हवा, बार–बार धूल भरी आंधियां, बढ़ते तापमान का रास्ता खुल जाएगाय इसके साथ खेती के कारण गहरे जमीनी पानी के खत्म होने से, मिट्टी का कटाव और तेज होगा, जिससे कृषि भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाएगी।

जहां अरावली को लेकर प्रस्तावित नए मानकों पर बहस खनन और पर्यावरण पर केंद्रित है वहीं लंबी अवधि की खाद्य सुरक्षा के लिए उभरता खतरा नजरअंदाज किया जा रहा है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन ने चेतावनी दी है कि मरुस्थलीकरण मिट्टी की उर्वरता को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे उपजाऊ जमीनें अर्धशुष्क हो जाती हैं। निश्चित रूप से, मरुस्थलीकरण इतना गंभीर मुद्दा है कि इसे सिर्फ दावों और वादों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। एक नई प्रबंधन योजना को लागू करने और 'मजबूत सुरक्षा' के वादे अब पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

निःसंदेह, अरावली की पहाड़ियां महज रणनीतिक खनिजों के लिए एक प्राकृतिक भंडार नहीं हैं, वे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करती हैं। प्रकृति प्रदत्त इन पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सेवाओं की वास्तविक आर्थिक लागत का पता नहीं लगाया गया है। एक बार जब यह मोल पता चल जाएगा, तो राष्ट्र को पहाड़ियों को बरकरार रखने की आर्थिक आवश्यकता का अहसास होगा, भले ही खनिजों को निकालने की आर्थिक लागत पर ज्यादा जोर दिया जाता है।

'द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी' के मानदंडों के अनुसार अगर राष्ट्रीय लेखा–जोखा में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कैलास पर्वत और डल झील को आर्थिक मूल्य दिया जा सकता है, तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के लिए भी, इसी प्रकार का लागत–लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए। ❑❑

(लेखक कृषि एवं खाद्य संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हैं।)

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/the-existence-of-aravalli-is-essential-for-food-security/

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ को समर्पित

काशी–तमिल संगमम

काशी तमिल संगमम एक ऐसे संबंधों का उत्सव है जो सदियों से भारतीय कल्पना में बसा हुआ है। असंख्य तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों के लिए, तमिलनाडु और काशी के बीच की यात्रा कभी भी केवल शारीरिक तौर पर आवागमन का माध्यम नहीं था – यह विचारों, सोच, भाषाओं और जीवित परंपराओं का एक आंदोलन था। संगमम इसी भावना से प्रेरित है, यह एक ऐसे बंधन को जीवित करता है जिसने पीढ़ियों से भारत के सांस्कृतिक वातावरण को शांतिपूर्वक आकार दिया है।

जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाए जाने के महत्व के बारे में गहराई और गंभीरता से विचार कर रहा था और अपनी सभ्यतागत विरासत की गहराई को फिर खोज रहा था। संगमम देश को जोड़ने वाली सांस्कृतिक निरंतरता को फिर से सशक्त करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास के तौर पर सामने आया। आत्मविश्लेषण और भारत की स्थायी शक्ति का उत्सव मनाने की इसी भावना के साथ, काशी तमिल संगमम ने एक पुराने जुड़ाव को सामने लाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच दिया, जिसने सदियों से आध्यात्मिक सोच, कलात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के आदान–प्रदान को मार्ग दिखाया है।

काशी तमिल संगमम की पहल "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सार को दर्शाती है, जो लोगों को अपनी संस्कृति से परे संस्कृतियों की समृद्धि को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित, आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, और रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, कपड़ा और युवा कार्य और खेल सहित दस मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी के साथ, काशी तमिल संगमम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरूओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक परम्पराओं को संरक्षित करने के लिए सभी को एक साथ लाता है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक कार्य प्रणालियों और पारंपरिक ज्ञान का आदान–प्रदान होता है। इस भव्य आयोजन के पीछे उद्देश्य यह था कि संगमम में समय–समय पर नए विषय जोड़े जाएं, नए और रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं और इसमें लोगों की भागीदारी भी ज्यादा से ज्यादा हो। प्रयास यही था कि यह आयोजन अपनी मूल भावना से जुड़े रहकर भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। वर्ष 2023 के दूसरे आयोजन में टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो कि इसमें भाषा कोई बाधा न बनने पाए। इसके तीसरे संस्करण में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष फोकस रखा गया।

काशी तमिल संगमम जैसे उत्सव भारत की विशाल सभ्यता और संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। इस संगमम की परिकल्पना को हम अपने निजी जीवन में भी आत्मसात कर सकते हैं।

– **विनोद जौहरी**

काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकाशी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है। पूज्य कुमारगुरुपरार स्वामीजी ने अपनी विद्वता और आध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त और स्थायी संबंध स्थापित किया था।

"काशी–तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ. इस बार की थीम बहुत रोचक थी– तमिल करकलम् यानि तमिल सीखें।" "इससे काशी और दूसरी जगहों

के लोगों को सुंदर तमिल भाषा सीखने का एक अनूठा अवसर मिला. तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने काशी के विद्यार्थियों के लिए इसे अविस्मरणीय बना दिया।

तमिल ग्रंथों को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया, "प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथ तोलकाप्पियम का चार भारतीय और छह विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया." "तेनकाशी से काशी तक पहुंची एक विशेष वाहन प्रदर्शनी भी देखने को मिली। काशी में स्वास्थ्य शिविरों और डिजिटल लिट्रेसी कैंप के आयोजन के साथ ही कई और सराहनीय प्रयास भी किए गए। इस अभियान में सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रसार करने वाले पांड्य वंश के महान राजा आदि वीर पराक्रम पांडियन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।"

अपने एक लेख में पीएम मोदी ने लिखा, "पूरे आयोजन के दौरान नमो घाट पर कई प्रदर्शनियां लगाई गईं, बीएचयू में शैक्षणिक सत्र का आयोजन हुआ, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। संगमम में इस बार जिस विषय ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता दी, वो हमारे युवा साथियों का उत्साह है। इससे अपनी जड़ों से और अधिक जुड़े रहने के उनके उत्साह का पता चलता है। उनके लिए ये एक ऐसा अद्भुत मंच है, जहां वे अलग–अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।"

तमिलनाडु से काशी की सुविधाजनक यात्रा के लिए ट्रेन चलाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा, "संगमम के अलावा काशी की यात्रा भी यादगार बने, इसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। भारतीय रेल ने लोगों को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए स्टेशल ट्रेनें संचालित की गयीं।

राष्ट्रीय एकता के लिए अहम बताते हुए श्री मोदी ने कहा, "इस बार काशी–तमिल संगमम का समापन समारोह रामेश्वरम में आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु के सपूत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने बेहतरीन विचारों से समृद्ध बनाया। उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह के मंच राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने इन संगममों को भारत की 'अनेकता में एकता' का उत्सव बताया, और काशी व तमिलनाडु के सदियों पुराने आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया, जिसमें संत कुमारगुरुपरार और कवि भारती का उल्लेख था।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने–कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। यह इसका प्रमाण है कि भारत के लोग जहां अपने इतिहास और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हैं, वहीं कभी हार न मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। यही भावना उन्हें एक साथ जोड़ती भी है। इस कार्यक्रम के दौरान उनकी भेंट कुछ ऐसे लोगों से भी हुई, जो सौराष्ट्र–तमिल संगमम के दौरान सोमनाथ आए थे और काशी–तमिल संगमम के समय काशी भी गए थे। 'मन की बात' के एक एपिसोड के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि अपने जीवन में तमिल भाषा न सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। हमारी संस्कृति में संगम का बहुत महत्व है। इस पहलू से भी काशी–तमिल संगमम एक अनूठा प्रयास है। इसमें भारत की विविध परंपराओं के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर अपने लेख में काशी–तमिल संगमम और सौराष्ट्र–तमिल संगमम जैसे प्रयासों को दो संस्कृतियों का मिलन करार दिया। साथ ही कहा कि आने वाले समय में इस आयोजन को और उज्जवल और जीवंत बनाया जायेगा।

कवि सुब्रमण्यम भारती और काशी के संबंधों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर दिखा। यहीं उनकी राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई, साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धार भी मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली।

वाराणसी में भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी आगे लिखते हैं, "यहां मैं काशी और उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों और बहनों की भी सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने काशी–तमिल संगमम को खास बनाने में अपना अद्भुत योगदान दिया है। उन्होंने अपने अतिथियों के स्वागत और सत्कार में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों के लिए अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए। वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये गर्व और संतोष दोनों का विषय है।"

काशी तमिल संगमम जैसे उत्सव भारत की विशाल सभ्यता और संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। इस संगमम की परिकल्पना को हम अपने निजी जीवन में भी आत्मसात कर सकते हैं। अपने जीवन में एक बार भारत दर्शन संभव हो सके और सम्पूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनन्द और दर्शन एक जीवन में संभव हो सके तो तमिल, तेलुगू, मलयालम, ओड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, उत्तरपूर्व की भाषाओं और संस्कृति से सम्मिलन और साक्षात्कार देश के वैभव को शिखर पर स्थापित कर सकेंगे। ❑❑

सुदृढ़ आर्थिकी के साथ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश

साल 2025 इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। प्रत्येक की तरह बीता साल भी कुछ मीठी–खट्टी, दुख–दर्द, हंसी–खुशी भरी यादें और उत्थान–पतन की कहानी छोड़कर गया है। प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं, जिनका व्यापक असर राज्य की जनता पर पड़ा। 2025 में राज्य में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं, अपराध, विकास कार्य, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हलचलों की कहानी काफी कुछ कहती है। पूरे साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी ने सभी दलों को जोर–शोर से सक्रिय रखा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश गौरव यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों का दौरा कर 5 करोड़ से अधिक लोगों को संबोधित किया। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय यात्रा चलाई, जिसमें अखिलेश यादव ने दो करोड़ युवाओं को जोड़ा। संभल और बरेली में कट्टरपंथियों की हिंसा से प्रदेश की छवि धूमिल हुई। वक्फ बोर्ड के नए कानून ने भी काफी हलचल बनाए रखी।

उधर, एक अन्य घटनाक्रम में अराजनैतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रदेश में लगनी वाली शाखाओं की संख्या बढ़कर 50 हजार हो गई, जिससे हिंदुत्व की लहर तेज हुई। कांग्रेस ने भी पुनरुत्थान की कोशिश की, लेकिन मात्र 5 फीसदी वोट शेयर के साथ असफल रही। महत्वपूर्ण घटना रही राम मंदिर का पूर्ण उद्घाटन हुआ, जहां 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इसी साल प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को भी नहीं भूला जा सकता है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित मेले में करीब सत्तर करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल थे।

आर्थिक उत्थान की नई ऊंचाइयां

उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से अधिक थी। एक जिला एक उत्पाद योजना से 20 लाख रोजगार सृजित हुए। लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे पर 500 नई इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 10,000 करोड़ का निवेश आया। कृषि क्षेत्र में सूर्यास्त से पहले बिक्री योजना से किसानों को 50,000 करोड़ का लाभ हुआ। 1 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। पर्यटन में अयोध्या का योगदान सबसे बड़ा रहा, जहां 2 करोड़ पर्यटक आए और 15,000 करोड़ की आय हुई। बुनियादी ढांचे में 10 नए हवाई अड्डे चालू हुए, जिससे निर्यात 30 प्रतिशत बढ़ा। महंगाई दर 5 प्रतिशत पर नियंत्रित रही, लेकिन बेरोजगारी 6 प्रतिशत पर स्थिर रही। कुल 25 लाख नौकरियां पैदा हुईं, जो राज्य को भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाया।

उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से अधिक थी।

–अजय कुमार

सामाजिक परिवर्तनों की लहर

सामाजिक क्षेत्र में 2025 ने कई मील के पत्थर गाड़े। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से लड़कियों का स्कूल नामांकन 95 प्रतिशत पहुंचा। 50 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गईं। जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई, जिसमें ओबीसी आबादी 52 प्रतिशत बताई गई। वहीं महिला सशक्तिकरण में 2 लाख स्वयं सहायता समूह बने, जिन्होंने 5,000

करोड़ का कारोबार किया। कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से शिशु मृत्यु दर 20 प्रति हजार घटी। ग्रामीण विद्युतीकरण 100 प्रतिशत हो गया, तीन करोड़ घरों में बिजली पहुंची। दलित-मुस्लिम एकता की घटनाएं बढ़ीं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव के 200 मामले दर्ज हुए। शिक्षा में 1,000 नए स्कूल खुले, साक्षरता दर 82 प्रतिशत हो गई।

अपराध और कानून व्यवस्था की चुनौतियां

कानून व्यवस्था में मिश्रित परिणाम आए। अपराध दर 15 प्रतिशत घटी, 2 लाख मामले दर्ज हुए। पुलिस मॉडर्नाइजेशन से 5,000 सीसीटीवी कैमरे लगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 गिरोहबाज जेल पहुंचे। वहीं महिला अपराधों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई, 50,000 मामले दर्ज। लव जिहाद के 1,000 केस सामने आए। साइबर अपराध 40 प्रतिशत बढ़े, 10,000 शिकायतें आईं। नार्को ड्रग्स जब्ती में रिकॉर्ड 500 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस भर्ती में 60,000 पद भरे गए। बीते साल खूंखार अपराधियों की मृत्यु से माफिया राज कमजोर हुआ। हालांकि, 100 पुलिस मुठभेड़ों में 200 अपराधी ढेर हुए, जिस पर विवाद रहा। कुल मिलाकर, अपराध नियंत्रण में 70 प्रतिशत सफलता मिली।

उत्थान-पतन की समग्र कहानी

2025 उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदों भरा साल साबित हुआ। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उछाल और विकास कार्यों ने राज्य को नई ऊंचाई दी। 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। चुनौतियां जैसे अपराध और बेरोजगारी बनी रहीं, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत हुई। भविष्य में 2027 चुनाव निर्णायक होंगे। योगी सरकार को 55 प्रतिशत लोकप्रियता मिली। सामाजिक एकता बढ़ी, लेकिन जातिगत समीकरण जटिल बने। कुल 2,500 करोड़ की कल्याण योजनाएं चलीं। यह साल इतिहास में विकास का वर्ष के रूप में दर्ज होगा, जहां दर्द के साथ खुशियां भी बंटीं।

आर्थिक उत्थान की नई ऊंचाइयां

उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ा। राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से अधिक थी। एक जिला एक उत्पाद योजना से 20 लाख रोजगार सृजित हुए। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 500 नई इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 10,000 करोड़ का निवेश आया। जबकि कृषि क्षेत्र में सूर्यास्त से पहले बिक्री योजना से किसानों को 50,000 करोड़ का लाभ हुआ। 1 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। पर्यटन में अयोध्या का योगदान सबसे बड़ा रहा, जहां 2 करोड़ पर्यटक आए और 15,000 करोड़ की आय हुई। बुनियादी ढांचे में 10 नए हवाई अड्डे चालू हुए, जिससे निर्यात 30 प्रतिशत बढ़ा। महंगाई दर 5 प्रतिशत पर नियंत्रित रही, लेकिन बेरोजगारी 6 प्रतिशत पर स्थिर रही। कुल 25 लाख नौकरियां पैदा हुईं, जो राज्य को भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाया। आवास योजना से 20 लाख गरीबों को घर मिले। जल जीवन मिशन से 5 करोड़ घरों में नल जुड़ें। सौर ऊर्जा क्षमता 10,000 मेगावाट पहुंची। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होने से लॉजिस्टिक्स लागत 30 प्रतिशत घटी। उद्योग नीति से 50 हजार करोड़ का निवेश आया। डिजिटल इंडिया से 90 प्रतिशत गांव इंटरनेट से जुड़े। पर्यावरण में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए। ये कार्य राज्य को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर ले गए।

बुलडोजर कार्यवाही

2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही को तेज किया। यह कार्यवाही मुख्य रूप से माफिया और उनके अवैध निर्माणों पर केंद्रित थी। सरकार का कहना था कि यह कदम राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए था। कई माफिया और गुंडे, जिनके पास बड़े अवैध निर्माण और संपत्ति थी, उन पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद भी उठे, और कई विपक्षी दलों ने इसे अवैध और तानाशाही करार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। राज्य सरकार ने पुलिस को और अधिक अधिकार दिए ताकि वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके परिणामस्वरूप, कुछ प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया।

सुधार की दिशा में कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसके अलावा, पुलिस स्टेशनों में तकनीकी उपकरणों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष कदम उठाए गए। महिला पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि की गई और महिला हेल्पलाइन की सुविधा को और प्रभावी बनाया गया। हालांकि, इसके बावजूद, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में कमी आने के बजाय उनका प्रतिशत कुछ हद तक बढ़ा। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास कार्यों पर जोर दिया। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में कई परियोजनाएँ शुरू की गईं। राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी योजनाओं की घोषणा की और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी। हालांकि, बेरोजगारी की समस्या अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी रही। ❑❑

नक्सलवाद का सिमटता दायरा

भारत एक विशाल, विविधता–पूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों के लोगों की अपनी–अपनी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच सत्तर के दशक में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद विचारधारा से प्रेरित एक आन्दोलन ने जन्म लिया, जिसने अपने आपको व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बताया – यही था "नक्सलवाद"। यह आंदोलन प्रारंभ में सामाजिक न्याय, भूमि सुधार और शोषण के विरुद्ध आवाज़ के रूप में सामने आया, परंतु समय के साथ यह हिंसक उग्रवाद में परिवर्तित हो गया। लंबे समय तक यह आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए व्यापक चुनौती बना रहा। लेकिन आज, निरंतर प्रयासों, नीतियों और विकास–योजनाओं के कारण नक्सलवाद का दायरा धीरे–धीरे सिमटता हुआ दिखाई देता है।

नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के "नक्सलबाड़ी" गाँव से हुई। भूमिहीन किसानों ने भूमि पर अधिकार की माँग करते हुए एक आंदोलन खड़ा किया। यह आंदोलन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित था और बाद में माओवादी सिद्धांतों की ओर उग्र रूप से अग्रसर हुआ। शुरुआती रूप में इसका संदेश– सामाजिक अन्याय, सामंती शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष – लोगों को आकर्षित करता था। किंतु जैसे–जैसे समय बीता, यह आंदोलन लोकतांत्रिक स्वरूप को छोड़कर हिंसा, धमकी, फिरौती, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाना और हथियारबंद संघर्ष की राह अपनाने लगा। इसी कारण इसे वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद कहा जाने लगा।

एक समय था जब नक्सलवाद अपने प्रभाव क्षेत्र में इतना विस्तृत था कि लगभग 200 से अधिक जिलों को "नक्सल प्रभावित क्षेत्र" माना जाता था। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ एक बड़ा भौगोलिक हिस्सा "लाल गलियारा" कहलाता था। इस क्षेत्र में शासन की पहुँच कमजोर थी, सड़क–बिजली–स्कूल–स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव था, जिससे नक्सलवाद को

भारत में नक्सलवाद का सिमटता दायरा केवल सुरक्षा बलों की सफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, विकास और सामाजिक न्याय की जीत भी है।

– दुलीचंद कालीरमन

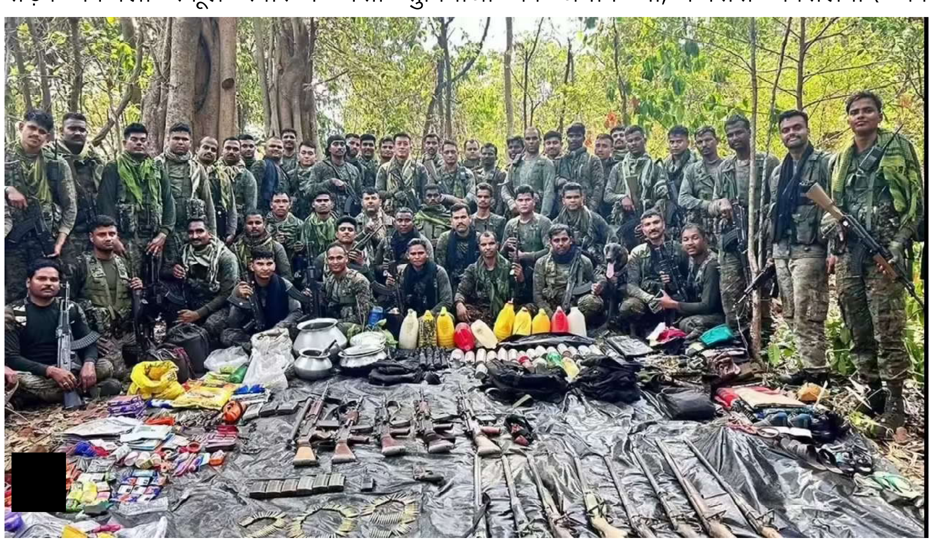

पनपने का अवसर मिला। जनता की मूलभूत आवश्यकताएँ जब पूरी नहीं होतीं, तब उग्रवादी विचारधाराएँ लोगों के बीच विश्वास जमा लेती हैं।

परंतु नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक में भारत ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा, विकास और विश्वास–निर्माण को आधार बनाया। वर्ष 2015 के बाद "राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना" के अंतर्गत ऑपरेशन "समाधान" लागू किया गया, जिसके माध्यम से आधुनिक तकनीक, ड्रोन निगरानी, उन्नत हथियार, पुलिस प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक कार्रवाई की गई। नक्सल संगठनों के शीर्ष नेताओं के मारे जाने या आत्मसमर्पण करने से उनका ढाँचा कमजोर हो गया।

नक्सलवाद के सिमटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण विकास की पहुँच का विस्तार रहा। जहाँ पहले नक्सली दावा करते थे कि वे आदिवासियों की आवाज़ हैं, वहीं अब जब सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार–योजनाएँ गाँवों तक पहुँचीं, तो लोगों की सोच बदली। आदिवासी युवाओं ने सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और नौकरियों का लाभ उठाया और मुख्यधारा से जुड़ने लगे। कई क्षेत्रों में जनता ने नक्सलियों का विरोध किया और सुरक्षा बलों का सहयोग किया।

इसके साथ–साथ सरकारों ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी शुरू की। इसमें नक्सलियों को हथियार छोड़कर सामान्य जीवन जीने का अवसर दिया गया– जैसे घर, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और नौकरी की सुविधा। हजारों नक्सलियों ने इस नीति का लाभ उठाकर हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। इसने नक्सलवाद की मानव–शक्ति और समर्थन दोनों को काफी हद तक कमजोर किया।

नक्सलवाद के सिमटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण विकास की पहुँच का विस्तार रहा। जहाँ पहले नक्सली दावा करते थे कि वे आदिवासियों की आवाज़ हैं, वहीं अब जब सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार-योजनाएँ गाँवों तक पहुँचीं, तो लोगों की सोच बदली।

यदि आज के परिदृश्य को देखें तो नक्सलवाद का सक्रिय क्षेत्र काफी कम हो चुका है। पहले जहाँ 200 से अधिक जिले प्रभावित थे, आज यह संख्या घटकर लगभग 40–45 जिलों तक सीमित रह गई है। इनमें भी गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की संख्या लगभग 8–10 ही बची है, जैसे – सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर आदि। यह आँकड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि नक्सलवाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक खतरा नहीं, बल्कि एक सीमित क्षेत्रीय चुनौती रह गया है।

हालाँकि यह कहना शीघ्र होगा कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अभी भी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों की कमी मौजूद है। यदि निरंतर प्रयास न किए जाएँ तो कठिन भू–भाग, घने जंगल वाले क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन आज भी नक्सलवाद के लिए जमीन तैयार कर सकता है। इसलिए जरूरत है कि सुरक्षा अभियान के साथ–साथ विकास, अधिकारों की सुरक्षा और जन–विश्वास को और अधिक मजबूत किया जाए।

भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग अपनी संस्कृति और अधिकारों के साथ मुख्यधारा के विकास का लाभ ले सकें। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, और जनता को यह महसूस हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके पक्ष में काम कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा स्पष्ट रूप से 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। समय–सीमा तय कर दी कि भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नक्सलियों बिना शर्त हथियार डालकर शांति अपनाने की अपील की है और सुरक्षा बलों को समय–सीमा के तहत नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सक्रिय रखने का निर्देश दिया है।

नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नक्सली नेताओं ने भी सामूहिक आत्मसमर्पण अभियान के तहत हाल ही में हथियार डाले हैं उनमे वेणुगोपाल राव, रुपेश, भास्कर आदि शामिल हैं। ये आत्मसमर्पण सरकार की सशस्त्र विद्रोह समाप्ति और पुनर्वास नीतियों के तहत हो रहे हैं। इसके अलावा माड़वी हिडमा और गणेश उइके जैसे कई नक्सल कंमाडर सुरक्षा बलों के हाथो मारे गए हैं। जिससे नक्सलवादी विचारधारा कमजोर पड़ी है और आदिवासी इलाकों में जनसमर्थन भी कम हुआ है।

भारत में नक्सलवाद का सिमटता दायरा केवल सुरक्षा बलों की सफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, विकास और सामाजिक न्याय की जीत भी है। यह तथ्य साबित करता है कि जब सरकार और जनता एकजुट होकर किसी समस्या को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, तो परिणाम अवश्य मिलता है। आज नक्सलवाद का दायरा सीमित हो चुका है और यदि निरंतर और संतुलित रणनीति जारी रही तो वह दिन अवश्य आएगा जब भारत पूरी तरह नक्सलवाद–मुक्त होकर शांति, समानता और प्रगति की राह पर और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ❑❑

चर्चा में है चीन और भारत की करीबी

चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है कि 'जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं'। अन्य विषयों के संदर्भ में इसका मोटा आशय यही है कि अगर समाज में कोई घटना होती है तो उसका असर सामाजिक व्यवहार शास्त्र, राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र पर भी पड़ता है। अमरीका ने भारत सहित कई देशों पर ट्रैरिफ वृद्धि की है। भारत के पड़ोसी चीन पर भी अमरीका ने शर्तें थोपी है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच साल 2025 में भारत और चीन के बीच होने वाले कारोबार को गति मिली है तथा भारत का निर्यात पहले की तुलना में बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 5.5 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा उच्चतम स्तर पर है लेकिन भारत की ओर से ठहरे हुए चीन को निर्यात में बढ़ोतरी से सकारात्मक संकेत मिलते हैं।

वर्तमान वैश्विक भू–राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अधिकांश देश आपस के छोटे–मोटे रगड़े से ऊपर उठकर वृहत्तर लाभ के लिए संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। भारत और चीन भी इस दिशा में लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष 2026 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया है और उन्होने आने का भरोसा भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा की है कि वैश्विक दक्षिण के हितों को ध्यान में रखते हुए अगला सम्मेलन सहयोग और स्थिरता के लिए क्षमता निर्माण और नवाचार पर केंद्रित होगा।

मालूम हो कि पूर्व में चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने हेतु गंभीर बातचीत के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। समझा जाता है कि दोनों देशों के सत्ताधारी दल आपसी समझदारी के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत और चीन के व्यापार में सबसे बड़ी समस्या व्यापार घाटे की रही है यानी कि भारत चीन को बेचता कम है, खरीदता ज्यादा है जो कि हमारे आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

भारत और चीन के मध्य जारी कूटनीतिक कोशिशों के बीच दोनों देशों के सत्ताधारी दलों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भेंट मुलाकात हुई। चीन के राजदूत की उपस्थिति में हुई भेंट के दौरान आपसी सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। यह अलग बात है कि भारत के विपक्षी दलों को यह भेंट हजम नहीं हुई। विपक्षी दलों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय राजनीति को ही प्रमुखता दी।

वास्तव में, भारत–चीन संबंधों को सामान्य बनाने का काम पिछले साल अक्तूबर में ही शुरू हो गया था, जब कजान में दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके बाद विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई। इन बैठकों में मुख्य रूप से सीमा पर तनाव, भारत–चीन व्यापार असंतुलन, हवाई सेवा ववीजा सेवा की पुनर्बहाली, द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही। तियानजिन शीर्ष स्तर पर इन्हीं मुद्दों पर विचार साझा करने का मंच बना, जिसके सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।

मौजूदा वैश्विक हालात के लिहाज से भी यह मुलाकात खासा अहम थी। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आर्थिक समीकरण तेजी से बदले हैं। इसका असर भारत और अमेरिका के संबंध पर भी पड़ा है। ऐसे में, पूरी दुनिया की नजर इस पर थी कि भारत और चीन जैसी दो बड़ी आर्थिक ताकतें अपने विवादों को किनारे करके किस गर्मजोशी के साथ बातचीत की मेज पर बैठती हैं। मोदी और जिनपिंग ने निराश नहीं किया। बैठक के बाद भारत और चीन की तरफ से जो अलग–अलग बयान आए, उनसे यही लगा कि संबंधों का नया दौर अब शुरू होने वाला है।

यह सही है कि उस मुलाकात के बाद कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं किया गया, लेकिन जो बातें कही गईं, उनमें काफी कुछ समानता थी। मसलन, दोनों देशों ने इसका स्वागत किया कि आपसी संबंध अब सुधरने लगे हैं। उन्होंने इस पर भी रजामंदी जताई थी कि गलवान झड़प के बाद सीमा पर पैदा हुए तनाव को खत्म करने में सफलता मिली है और वहां शांति व स्थिरता आई है। यह स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप की नीति और सीमा पर सुधरते हालात ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध–सुधार के आधार बने हैं।

हालांकि, अब भी कई ऐसे मसले हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं। पहला, आपसी विश्वास बहाली के उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा विश्वास नहीं जम सका है। दूसरा, सीमा पर शांति व स्थिरता तो बहाल हो गई, मगर असली मुद्दा सीमा–विवाद का समाधान है। सीमा समझौते अब हो जाने चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व विशेष प्रतिनिधि के स्तर पर जो बातचीत चल रही है, उसे अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए।

भारत ने कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता एक 'बीमा पॉलिसी' है, जो द्विपक्षीय संबंध में सुधार के लिए जरूरी है, जबकि चीन सीमा विवाद को अपेक्षाकृत कम तवज्जो देते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वकालत कर रहा है। विचारों का यह अंतर बताता है कि चीन जहां आपसी रिश्ते को तत्काल गति देना चाहता है, वहीं नई दिल्ली फूंक–फूंककर कदम आगे बढ़ाने की इच्छुक है। मतभेद को 'विवाद का रूप न देने की बात भी कही गई, साथ ही चीन ने भारत की इस सोच पर हामी भरी कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की जरूरत है।

मुलाकात से यह संदेश भी निकला था कि दोनों देश एक–दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों एक–दूसरे के यहां निवेश बढ़ाने को भी तैयार हुए हैं। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों देशों में विश्वास बहाल हो गया है। यह काफी कुछ सीमा के हालात और विशेष प्रतिनिधियों की आपसी बातचीत पर निर्भर करेगा। चूंकि अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारे पास है, जिसका अगला सम्मेलन भारत में होगा, लिहाजा मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है, जिसका मतलब है कि इस साल फिर से दोनों शासनाध्यक्षों की बैठक होगी, जहां से इस बदलते रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है।

दोनों देशों के संबंध में एक पहलू पाकिस्तान भी है। आतंकवाद पर ठीक–ठाक बातचीत होनी चाहिए। चूंकि, दोनों देश यह चाहते हैं कि किसी तीसरे देश के नजरिये से आपसी संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए, इसलिए भारत की जहां यह सोच होगी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को चीन दरगुजर करे, तो उसी तरह बीजिंग की भी मंशा यही होगी कि पाकिस्तान–चीन रिश्ते का असर भारत–चीन संबंध पर न पड़े। हालांकि, चीन के साथ रिश्तों में सुधार का दीर्घकालिक लाभ हमें जरूर होगा, पर इतिहास को देखते हुए लगता यही है कि सुधार की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होने वाली है, जिसमें कई उतार–चढ़ाव आ सकते हैं।

बहरहाल भारत सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में चीन के साथ भारत के निर्यात बढ़ने की पुष्टि हुई है। वहीं चीन के कस्टम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में भी 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षी व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 155.62 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन हमें यहां यह याद रखना होगा कि भारत और चीन के व्यापार में सबसे बड़ी समस्या व्यापार घाटे की रही है यानी कि भारत चीन को बेचता कम है, खरीदता ज्यादा है जो कि हमारे आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है। ❑❑

ईरानी बहनें तोड़ रही बुर्का की जंजीरे, भारत में बढ़ रही है कट्टरता

ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का साहसी विद्रोह पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है, जहां कुरान के नाम पर थोपी गई बुर्का और नकाब जैसी परंपराओं के खिलाफ सड़कों पर आवाज़ उठ रही है। खामेनेई की तानाशाही वाली सरकार के सामने ईरानी महिलाएं बिना नारे लगाए, बिना हिंसा किए, बस सिर से दुपट्टा उतारकर सड़कों पर उतर आई हैं, जो महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद 2022 से चला आ रहा आंदोलन अब 2025–2026 में और तेज हो गया है। यह बगावत न केवल ईरान तक सीमित है, बल्कि अरब और अन्य मुस्लिम देशों में भी बुर्का हटाने की हवा चल रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे स्थानों पर इसके पक्ष में कट्टरता बढ़ रही है। यह और बात है कि इन देशों के मुसलमानों को अरब जगत मुस्लिम मानने को ही नहीं तैयार होता है।

गौरतलब हो, ईरान को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है, जहां 1979 की क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने कुरान आधारित शासन स्थापित किया और महिलाओं पर सख्त हिजाब अनिवार्य कर दिया। नैतिक पुलिस द्वारा सड़कों पर गश्त कर महिलाओं को पकड़ना और सजा देना आम हो गया, लेकिन 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में संदिग्ध मौत ने चिंगारी जला दी। उसके बाद लाखों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर दुपट्टा जलाया, बाल कटवाए और नारे लगाए, जिससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया। हालिया समाचारों के अनुसार, दिसंबर 2025 में तेहरान और अन्य शहरों में महिलाएं खुलेआम बिना दुपट्टे के घूम रही हैं, जो सरकार को डरा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने विवादास्पद हिजाब कानून को स्थगित कर दिया, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनेई के दबाव में सैन्य बल तैनात हैं। प्रदर्शनों में कम से कम छह मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर भी महिलाओं का खामोश विरोध जारी है।

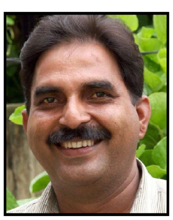

वैश्विक स्तर पर 16 देशों के प्रतिबंध से संदेश साफ है कि बुर्का महिलाओं के उत्पीड़न का प्रतीक माना जा रहा।

– संजय सक्सेना

बहरहाल, यह आंदोलन सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम के नाम पर थोपी गई कट्टरता के खिलाफ जागृति का प्रतीक है। अरब प्रायद्वीप से इस्लाम फैला, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल रही है, जहां अब पूर्ण बुर्का अनिवार्य नहीं। मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कजाकिस्तान, जहां 70 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, ने 2025 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का–नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जुर्माना 10 हजार से एक लाख रुपये तक। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने पहले ही चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा रखी है, ताकि धार्मिक कट्टरपंथ न फैले। कुल 16 से अधिक देशों ने बुर्का या नकाब पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड ने 2021 के जनमत संग्रह में 51.21 प्रतिशत वोटों से 2025 में इसे लागू किया, जबकि फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया, इटली और जर्मनी ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर

जुर्माना या जेल की सजा निर्धारित की। बेल्जियम में मात्र 300 महिलाएं ही बुर्का पहनती थीं, फिर भी 10 लाख मुसलमानों के बीच इसे प्रतिबंधित किया गया।

इसके विपरीत, दक्षिण एशिया में स्थिति उलटी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में, जहां इस्लाम स्थानीय रूप से फैला, वहां कट्टरता बढ़ रही है। भारत के बिहार में हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का दुपट्टा हटाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तक से विरोध के सुर उठे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाएं दुपट्टा या बुर्का पहनने को धार्मिक अधिकार बताकर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वहां के सर्वेक्षणों में 60–70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे स्वैच्छिक बताती हैं, लेकिन कट्टर समूह दबाव बनाते हैं। भारत में कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद स्कूल–कॉलेजों में बहस चली, जहां मुस्लिम छात्राओं ने पहनने पर जोर दिया। यह विरोधाभास दर्शाता है कि जहां मूल इस्लामिक केंद्रों में महिलाएं आजादी चाह रही हैं, वहीं यहां आयातित कट्टरता बुर्का को मजबूरी बना रही है।

सऊदी अरब में भी महिलाएं ड्राइविंग और बिना नकाब के घूमने की मांग कर रही हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में तस्वीर उलट है। यहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में मुस्लिम महिलाएं उसी हिजाब या बुर्का को धार्मिक फर्ज बताकर प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान में हाल ही में लाहौर और कराची की सड़कों पर महिलाओं ने जुलूस निकाले। वे कह रही हैं कि स्कूलों में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहां के सर्वे बताते हैं कि साठ से सत्तर प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी मर्जी से पहनती हैं। लेकिन कट्टर गुट दबाव बनाते हैं। पड़ोसियों की नजरें, मौलवियों की फतवे और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से कई लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्राओं ने हिजाब अनिवार्य करने की मांग की। वहां भी तहरीक–ए–तालिबान जैसे संगठन पीछे हैं। महिलाएं कहती हैं कि बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं करेंगी। लेकिन गुप्त सर्वेक्षणों में पता चलता है कि आधी से ज्यादा लड़कियां इसे बोझ मानती हैं। फिर भी भीड़ का दबाव उन्हें चुप करा देता है।

भारत में कर्नाटक का हिजाब विवाद तो चरम पर पहुंच गया। उदुपी के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं ने कक्षा में घुसने से इनकार कर दिया। वे दुपट्टा या हिजाब के बिना परीक्षा नहीं देंगे, ऐसा हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के पीछे जमीयत उलेमा–ए–हिंद जैसे संगठन थे। कोर्ट ने फैसला दिया कि यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है, लेकिन बहस थम नहीं रही। मंड्या, बीदर जैसे जिलों में स्कूलों के बाहर जुलूस हुए। छात्राओं के माता–पिता भी सड़क पर उतरे। वे चिल्ला रहे थे– हमारी बेटियों का धर्म सुरक्षित रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियां डर से हिजाब पहनती हैं। पड़ोस के हिंदू–मुस्लिम तनाव में इसे ढाल बना लिया जाता है।

उक्त देशों में यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। जहां दुनिया महिलाओं को सशक्त बना रही है, वहां दक्षिण एशिया में कट्टरता उन्हें पुराने जंजीरों में जकड़ रही। सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं। लेकिन अल्पसंख्यक कट्टर गुट बहुमत को दबा रहे हैं। क्या यह धार्मिकता है या राजनीति? नेताओं को चाहिए कि वे तथ्यों पर ध्यान दें। महिलाओं को चुनाव दें– पहनें या न पहनें। तब सच्ची तस्वीर सामने आएगी। अन्यथा यह आयातित आग स्थानीय संस्कृति को भस्म कर देगी। दक्षिण एशिया की महिलाओं को मूल आजादी मिलनी चाहिए, न कि मजबूरी।

बात ईरान में आए बदलाव की कि जाए तो इसके पीछे गहन कारण हैं। ईरान जैसे देशों में आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने महिलाओं को जागृत किया, जहां प्रदर्शनों में आजीविका की मांगें भी जुड़ गईं। मुस्लिम बहुल देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाना बनाकर बुर्का प्रतिबंध बढ़ा, क्योंकि चेहरा ढका होना अपराध को आसान बनाता है। वैश्विक स्तर पर 16 देशों के प्रतिबंध से संदेश साफ है कि बुर्का महिलाओं के उत्पीड़न का प्रतीक माना जा रहा। दक्षिण एशिया में कट्टरता का कारण विदेशी धन–सहायता और राजनीतिक उन्माद है, जहां बांग्लादेश–पाकिस्तान में मदरसों से प्रेरित युवतियां बुर्का को पहचान बना रही हैं। ईरानी महिलाओं की बगावत ने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम के नाम पर थोपी गई परंपराएं टूट रही हैं। यदि यह लहर फैली, तो कट्टरता वाले क्षेत्रों में भी परिवर्तन अपरिहार्य होगा। आंकड़ों से सिद्ध है कि जहां प्रतिबंध लगे, वहां महिलाओं की भागीदारी 20–30 प्रतिशत बढ़ी है। यह संघर्ष स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ❑❑

भारत की संप्रभुता सर्वोपरि

खौफनाक नारेबाजी पर सख्ती जरूरी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है। ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव भी इन्हीं पर टिकी होती है। भारतीय संविधान सभा ने प्रारंभ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया था, क्योंकि यह स्वराज की मांग का मूल तत्व माना जाता था।

देश में समय–समय पर राजद्रोह कानून को लेकर चर्चा होती रहती है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजद्रोह कानून का प्रयोग ऐसे उकसावे वाली नारेबाजी के मामले में किया गया, जो अंततः राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं। इसी संदर्भ में बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल का एक निर्णय चर्चा के केंद्र में है। न्यायमूर्ति देशवाल ने 'गुस्ताख–ए–नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे नारे को लेकर कहा कि यह लोगों को हिंसक विद्रोह के लिए भड़काने की मंशा से जुड़ा है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देता है, इसलिए इस पर राजद्रोह का आरोप लगाना उचित ही है।

यह मामला बरेली में इस साल 26 सितंबर की एक घटना से जुड़ा हुआ है। आल इंडिया इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौसीफ रजा ने उस दिन जुमे की नमाज के बाद शहर के इस्लामिया इंटर कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और झूठे मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने आयोजकों को सूचित किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

प्रशासन के इस हस्तक्षेप से उत्तेजित भीड़ ने पत्थरबाजी, फायरिंग से लेकर पेट्रोल बम तक फेंकने शुरू कर दिए। उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक तथा निजी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है।

– संध्या जैन

संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस दौरान उत्तेजित भीड़ 'गुस्ताख–ए–नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' का नारा भी लगाती रही। काउंसिल के नेता नदीम खान ने भी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद इस्लामिया इंटर कालेज की ओर कूच करने के लिए लोगों को उकसाया। लगभग पांच सौ लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें इस्लाम के नबी के अपमान से जुड़ा विवादास्पद नारा भी शामिल था।

सार्वजनिक व्यवस्था में गतिरोध पैदा करने के लिए नागरिकों को उकसाना राष्ट्र के सामाजिक ताने–बाने को खतरे में डालता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का यह अर्थ नहीं कि इससे लोगों को कानून को चुनौती देने और दूसरों के प्रति हिंसा एवं उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसी नारेबाजी के आरोपितों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून एवं व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि किसी धर्म, पंथ या मजहब के आराध्य का अपमान होता है तो यह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 और अन्य धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है।

जबकि किसी भी धर्म या ईश्वर के प्रति निंदात्मक कृत्य (ब्लासफेमी) बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत दंडनीय अपराध है। बीएनएस का अध्याय 16 बहुत व्यापक स्वरूप लिए हुए है और इसमें धर्म–पंथ से संबंधित लगभग सभी अपराधों का समावेश किया गया है। जैसे किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना–स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना (धारा 298), किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने वाले सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण कृत्य (धारा 299) एवं किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ अपमानजनक शब्दों का उच्चारण आदि (धारा 302) प्रमुख हैं। धर्म या धार्मिक प्रतीकों के विरुद्ध इन अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत तीन से पांच वर्ष तक के कारावास का प्रविधान किया गया है।

किसी भी धर्म या ईश्वर के प्रति निंदात्मक कृत्य (ब्लासफेमी) बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत दंडनीय अपराध है। बीएनएस का अध्याय 16 बहुत व्यापक स्वरूप लिए हुए है और इसमें धर्म–पंथ से संबंधित लगभग सभी अपराधों का समावेश किया गया है।

'गुस्ताख–ए–नबी...' के नारे की बात की जाए तो यह नबी के अपमान पर ऐसा करने वाले का सिर काटने का आह्वान करता है। सबको पता है कि अभी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ? यह नारा भारत और भारतीय कानूनी प्रणाली की संप्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को जाति, धर्म या पंथ के बावजूद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य–अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति लोगों को ऐसी सजा देने के लिए उकसाने का प्रयास करता है, जिसका आपराधिक कानूनों में कोई उल्लेख ही नहीं तो स्पष्ट रूप से वह अवैध है। उकसावे की ऐसी कोई भी कवायद या आह्वान बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है।

देखा जाए तो 'गुस्ताख–ए–नबी की एक सजा...' का कोई आधार कुरान या हदीस में नहीं मिलता है। इसकी जड़ें तो पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून से जुड़ी हुई मिलती हैं। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला आसिया बीबी को 2011 में ईशनिंदा कानून में दोषी ठहराया गया था। पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने इसका विरोध किया तो उसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। उस समय मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी की अगुआई में इकट्ठा हुई भीड़ ने पहली बार यह नारा लगाया, जो बाद में भारत सहित अन्य तमाम देशों में फैलता गया। अन्य धर्मों के लोगों को डराने, हिंसक विद्रोह के लिए उकसाने तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देने के लिए इस नारे के दुरुपयोग की निंदा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 17 दिसंबर को अभियुक्तों को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है। ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव भी इन्हीं पर टिकी होती है। भारतीय संविधान सभा ने प्रारंभ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया था, क्योंकि यह स्वराज की मांग का मूल तत्व माना जाता था। हालांकि शीघ्र ही सदस्यों ने सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं की दूरदृष्टि को समझा, जो असीमित वाक्–स्वातंत्र्य पर यथोचित नियंत्रण के पक्षधर थे। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से राजद्रोह को पुनः कानून में शामिल किया। ❑❑

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

स्वामी विवेकानंद जयंती पर विशेष

क्रांतिकारी विचारों का सन्यासी

स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर हम उनके जीवन उनके कामकाज और उनके सिखाए तकनीकी तरीकों के आधार पर अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। स्वामी जी के विशाल जीवनानुभवों और अल्पायु में किए गए बेशुमार कृत्यों के आलोक में एक अचरजकारी सवाल जरूर उठता है कि आखिर वे इतना सब कुछ इतनी छोटी आयु मात्र 39 साल के जीवन खंड में वह कैसे कर सके थे? क्या यह सब स्वामी जी के समय प्रबंधन का कौशल था? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर यह सब उनके समय प्रबंधन का ही कमाल था तो निश्चित ही उनके कुछ सूत्र आज प्रबंधन के बोलबाला वाले दौर में और भी उपयोगी हो सकते हैं। आइए, उनकी जयंती के अवसर पर विचार करते हैं कि उनके व्यवस्था सूत्र क्या है?

विवेकानंद चाहते तो वह भी लालची वकील होकर बेशुमार धन–दौलत कमा सकते थे। बावजूद उन्होंने समाज, देश के लिए त्यागमय जीवन को चुना।

–अनूप पाण्डेय

सक्रियता

स्वामी विवेकानंद आरंभ से ही कर्म की अहमियत देते थे। जीवनकाल में दिए गए उनके हरेक भाषणों और वार्तालापों में वह बारम्बार स्व–कर्म करने के लिए लोगों से अपील करते थे, उन्हें निर्देश तक देते थे। दरअसल, वह जीवन में स्वाभाविकं कर्म करने का तकाजा करते थे। स्वामी जी ने तत्कालीन भारत के समक्ष मुंह बाए खड़ी चुनौतियों–गरीबी, भूख, अशिक्षा, अंधविश्वास और धर्म, जाति और क्षेत्रीय अलगाव–को चिह्नित कर रखा था। वह इस बात पर क्षोभ व्यक्त करते थे कि किस तरह भारतवर्ष अपने ऐतिहासिक गौरव के शिखर से विदेशी कुशासन के गर्त में गिर कर आर्थिक और सामाजिक; दोनों क्षेत्रों में पराभव को प्राप्त हो गया था।

आत्मनिरीक्षण

विवेकानंद ने हमेशा व्यक्ति के आत्मावलोकन पर बल दिया। वह खासकर अपने समानधर्मी हिन्दुओं से बहुत नाराज थे और उन्हें अधिक आत्मनिरीक्षण करने पर जोर देते थे। घुसपैठिये विदेशी शासकों और साम्राज्यवादियों से देश के आक्रांत होने के लिए हिन्दुओं को ही कसूरवार मानते थे। उन्होंने बताया कि हिन्दुओं में आंतरिक अलगाव, परस्पर दुश्मनी, एक दूसरे के विरुद्ध छल–छद्म और घोर निठल्लेपन का फायदा उठाकर ही विदेशी हम पर हुकूमत करने लगे थे। स्वामी जी ने हिन्दुओं और मुसलमानों से अपने वैर–भाव भुलाकर राष्ट्र के नवनिर्माण में जुट जाने का आह्वान किया। वह हमेशा हिन्दू मस्तिष्क और इस्लामी काया के सहमेल की बात करते थे। बहुतेरों ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच सद्भाव और सहयोग कायम करने में इस मुहावरे के उपयोग को चमत्कारिक माना है। वहीं कुछ लोगों ने इस मुहावरे पर आपत्ति जताई। उनका सवाल था कि स्वामी जी के कहने का मतलब हुआ कि

हिन्दुओं में शारीरिक बल नहीं होता और मुसलमान बौद्धिक नहीं होते। हालांकि प्रबंधक शरीर और मन के अपने विशिष्ट बल होने के विचार को समझेंगे और दोनों को एक साथ रखेंगे, जहां एक और एक का जोड़ दो से बहुत ज्यादा 11 हो सकता है।

जवाबदेही

स्वामी विवेकानंद ने देश की गरीबी और गरीबों की दुर्दशा के लिए तब के सम्पन्न भारतीयों को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था, इन भूखे, नंगे और आश्रयहीन लोगों के रहते अघाए लोगों की प्रार्थना, पूजा–पाठ और तीर्थाटन एक पाखंड है। गरीबों के आगे धर्म–चर्चा उनका उपहास करना है। उनके इस कहे का यह मतलब नहीं कि वह मनुष्य की भौतिकेतर आवश्यकताओं से अनभिज्ञ थे। उनका मानना था कि मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक रास्ते पर कदम बढ़ाने के पहले बुनियादी और सहज भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। स्वामी जी ने साफ कहा कि गरीबों का यह हक ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि वह कुलकों के विरुद्ध विद्रोह कर दें। यहां विवेकान्द हमें समाजवादी और मानवतावादी लगते हैं।

वैश्वीकरण

19वीं सदी में देश के दूर–दराज के इलाकों में भ्रमण और समुद्री मार्ग से विदेश यात्रा करना काफी दुष्कर था। लेकिन स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में वेदांत का संदेश पहुंचाने के लिए उतावले थे। इसके लिए उन्होंने पहले दक्षिण भारत की यात्रा की और वहां से अमेरिका जाने के लिए धन और सहायता जुटायी। शिकागो में न केवल उन्होंने धर्म संसद पर अपने अपनत्व भरे संबोधन, गुरुत्तर ज्ञान और ओजस्वी भाषण से अपनी अमिट छाप छोड़ी बल्कि इन गुणों के कारण समूचे अमेरिका में वह छा गए।

प्रभावी संवाद शैली

स्वामी विवेकानंद महान वक्ता थे। सीधे मर्म को छू लेने वाली प्रखर अभिव्यक्ति कला से पहले उन्होंने पूरे भारत में अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने बिना थके मीलों दूर तक यात्राएं की और बिना विराम लिए लोगों को संबोधित करते रहे। वह देश–दुनिया के लाखों लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने के महत्त कार्य के लिए अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक दिये गए उनके भाषणों का संग्रह, उनके तप मिशन का जीवंत अभिलेख है। वह संजीदगी से बोलते थे। वे वेधड़क, दो टूक बोलने वाले और परिस्थिति–मुताबिक रूखे होकर वाद–विवाद तक कर लेते थे। लोगों से उनका अनथका संवाद भारत से अमेरिका और फिर वहां से पूरे विश्व में फैल गया।

संस्थाओं का निर्माण

स्वामी विवेकानंद घूम–घूम कर बोलते ही नहीं रहे; उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के नाम पर पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की गौरवशाली कालजयी संस्था की नींव रखी। बेलूर रामकृष्ण मिशन का मूल निवास है। पार्श्व में बहती हुगली नदी के किनारे टीन की छत से ढंका छोटे–से घर को आज भी आबाद रखा गया है, जहां स्वामी जी ने पांच संन्यासिनों के साथ मिलकर रामकृष्ण मठ की आधारशिला रखी थी। अब तो इस संस्था का वैश्विक अवतार हो गया है, जहां सान्फ्रांसिकों से लेकर सिडनी तक 250 आश्रम हैं।

रामकृष्ण मठ सभी लिहाज से महान संस्था है। इसने स्वामी जी के अखिल विश्व को एकल मानवीय परिवार मानने के वेदांत के उनके दृष्टिकोण को सच्चे अर्थों में साकार किया है। इसने मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नयन के काम को ही व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया है बल्कि गरीबों की शिक्षा और उन्हें स्वास्थ्य देने का दायित्व भी निभा रहा है। रामकृष्ण मिशन अपने मूल मूल्यों और संस्कृति को आत्मसात किए हुए है।

नेतृत्त्व के गुण

स्वामी विवेकानंद विचार, शब्द और कर्म से एक सम्पूर्ण नेता थे। वह संवाद करते थे। वह हमेशा अगले मोर्चे पर मिलते थे। श्रीरामकृष्ण परमहंस के महान, समग्र और आंतरिक विश्वासों से भरपूर आध्यात्मिक संदेशों को जन–जन तक पहुंचाना स्वामी जी के प्रयासों से ही संभव हुआ। सुंदर उपमाओं से लिखी धर्म सिद्धांत की उनकी पुस्तक व्यापक तौर पर पढ़ी जाती है और उन पर चर्चा की जाती है। इसने फ्रेंच के ख्यातिलब्ध विद्वान रोम्या रोलां का ध्यान खिंचा, जिन्होंने 'लाइफ ऑफ विवेकानन्द' नामक किताब लिखी और इस तरह स्वामी जी को दुनिया के पाठकों के बीच ले गए।

एक लक्ष्य

स्वामी जी ने कानून की पढ़ाई की थी। वकालत उस समय का सबसे सम्मानित पेशा माना जाता था। तेज–तर्रार वकीलों की अच्छी खासी फीस भी होती थी। हालांकि तब स्वाधीनता संग्राम के सेनानी होने के लिए अनेक वकीलों ने अपने पेशे का त्याग कर दिया था। स्वामी जी उन सबके अग्रदूत थे।

विवेकानंद चाहते तो वह भी लालची वकील होकर वेशुमार धन–दौलत कमा सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने समाज, देश के लिए त्यागमय जीवन को चुना। वह आजीवन श्रीमद्भगवद्गीता के मूल निष्काम भाव से स्वकर्म, का पालन करते रहे। इसके चलते ही वह मर कर भी अमर हो गए। ❑❑

12 जनवरी विवेकानंद जयंती पर विशेष

विवेकानंद एक सशक्त स्त्रीवादी

हम स्त्री सशक्तीकरण के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। आज से लगभग डेढ़ सदी पहले एक युवा और घुमक्कड़ संन्यासी स्वामी विवेकानंद ने पाया था कि भारतीय नारियों की दशा दीन–हीन है। उन्हें इसकी मूल वजह स्त्री–अशिक्षा लगी थी। तभी वह इसे मिटाने की धुन में लग गए थे। स्वामी ने तय किया कि एक दिन वह स्त्रियों की इस दुर्दशा को दूर करके रहेंगे और उन्हें एक पढ़ा–लिखा परिवेश देंगे। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद के मंच से मौजूदा श्रोतावर्ग को गरिमामय और अपार स्नेह से 'अमेरिका की बहनों एवं भाइयों' कह कर पश्चिमी जगत के प्रबुद्ध मानस को जीत चुके थे। पश्चिमी समाज में स्त्री को मान–सम्मान प्राप्त था और उन्हें उनके बेहतर भविष्य के लिए एक आश्वासन था। धर्म संसद को संबोधित करने के पहले स्वामी जी मैसाच्यूट्स के ब्रीजी मेडोज में संवाद कर चुके थे, जहां उन्हें सुनने महिला जेल की एक कैदी भी आई थी। इस बैठक में विवेकानंद ज्यादा समय तक भारतीय नारियों और उनकी वीरता का बखान करते रहे किंतु उनका ध्यान उनकी मौजूदा अधोगति से उबारने के प्रयासों पर भी था।

पढ़ाई–लिखाई : बेड़ियां तोड़ने का सूत्र

गरीब–लाचार, निरक्षरता की सजा भुगत रही और वर्चस्ववादी पुरुषप्रधान समाज में तिरस्कृत रहने वाली भारतीय नारियों के लिए तब क्या कोई उम्मीद थी? शिक्षित अमेरिकी स्त्रियों के प्रखर आत्मविश्वास को देखकर ही स्वामी को यह सूत्र मिला कि भारतीय नारियों की दुर्दशा को दूर करने की वह कुंजी शिक्षा ही हो सकती है। उन्होंने भारत में अपनी बहनों को रूढ़िवाद की बलिवेदी पर आत्महत्याएं करते देखा था। लेकिन स्वामी जी अमेरिकी स्त्रियों के व्यवहारों पर गौर करते हुए इस धारणा पर भी पहुंचे थे कि भारतीय नारियों को

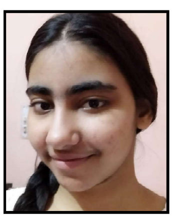

शिक्षित अमेरिकी स्त्रियों के प्रखर आत्मविश्वास को देखकर ही स्वामी को यह सूत्र मिला कि भारतीय नारियों की दुर्दशा को दूर करने की वह कुंजी शिक्षा ही हो सकती है।

–वैदेही

पश्चिम के बिना सोचे–समझे अनुकरण से परहेज ही करना चाहिए। न्यूयार्क में एक सभा में स्वामी ने बेबाक कहा, 'मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाएं आपकी स्त्रियों जैसी बौद्धिक हों लेकिन अवश्य ही यह शुद्धता की कीमत पर न हो।' कैलिफोर्निया में स्वामी जी ने 1990 में अपने एक व्याख्यान में कहा, 'भारत में आदर्श नारी मां है–वह पहले और आखिर में सिर्फ मां है।

'स्त्री' शब्द के उच्चारण मात्र से ही एक आम हिन्दू के मन में जो पहली छवि बनती है, वह मां की है और ईश्वर को मां कहा गया है।' इसी तरह, अगर मां शिक्षित और आत्म–विश्वासी नहीं होगी तो फिर वह आदर्श मां कैसे बन सकेगी? यही वह बड़ी वजह थी, जिसने स्वामी विवेकानंद को स्त्री सशक्तीकरण जैसे बड़े मकसद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पाया कि वह आजाद जन्म लेकर भी, स्त्री हर तरफ बेड़ियों से जकड़ी हुई है। यहां तक कि सम्पन्न घराने की महिलाएं भी कई रूपों में समाज के दबाव के आगे नतमस्तक थीं। जाहिर था कि लड़ाई दुधारी थी। एक तरफ तो आत्भज्ञान सम्पन्न लोगों का यह कर्त्तव्य बनता था कि वे बाल विवाह और विधवाओं के प्रति अपने रूढ़ विचारों को छोड़ें। स्वामी जी का कहना था, 'स्मृतियों की रचना कर और उनमें स्त्रियों के लिए कड़े–कड़े नियमों के प्रावधान कर पुरुषों ने स्त्रियों को केवल संतान पैदा करने वाली मशीन बना कर रख दिया है।'

स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम

दूसरी तरफ, उनका यह भी मानता था कि स्त्रियों को खुद भी अपनी दासता से उबरने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए स्त्री को पढ़ाने–लिखाने की जरूरत थी, जिससे कि वह मानवाधिकारों को जान सके। साथ ही घर–बार संभालने में एक रचनात्मक जोड़ीदार बने। ऐसी स्त्री–शिक्षा के योग्य पाठ्यक्रम को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में स्वामी जी ने –कहा था, 'स्त्री शिक्षा में धर्म, कला, विज्ञान, घर के कामकाज, रसोई, बुनना, स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल' के ज्ञान देने वाले पाठ रहेंगे और निश्चित रूप से महाकाव्यों की वीरांगनाओं के अध्याय भी दिए जाएंगे। वह चाहते थे कि स्त्रियों को ऐसी सर्वांगीण शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण केंद्र चलें।

समाज के लादे प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता को भारत आने का आमंत्रण दिया और उनसे स्त्री शिक्षा के लिए काम करने को कहा। तत्कालीन भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भगिनी निवेदिता और भगिनी क्रिस्टिन का अमूल्य योगदान इतिहास में दर्ज है। उन सभी मामलो में स्वामी विवेकानंद का नजरिया बेबाक था। जब उनसे पूछा गया कि इन पढ़ी–लिखी स्त्रियों का मौजूदा सामाजिक बंधन वाले हालात में शादी–ब्याह हो पाएगा, विवेकानंद ने कहा था कि जब कोई काम नैतिक बल के साथ किया जाता है तो निश्चित सफलता मिलती है। आपने समाज के चलन को समझा नहीं है। इन विद्वान और सुसंस्कृत लड़कियों के लिए लड़कों का अकाल नहीं होगा। आज का समाज बाल विवाह को पसंद नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा।'

सशक्त इतिहास बोध

तत्कालीन समाज में ब्रह्मचारिणी बनकर उपलब्धि पाने का भी एक मार्ग था और इस तरह समाज के लिए अपने को उपयोगी बनाना था। विवेकानंद का इतिहास बोध बड़ा सशक्त था। वह जानते थे कि भारत की महानता यहां समाज को दिए गए स्वियों के अप्रतिम अवदान पर आश्रित है। लाख बाधाओं के बावजूद भारतीय नारियां स्वाभाविक रूप से अध्यात्म की ओर उन्मुख थीं और अपनी ऐतिहासिक–पौराणिक महान वीरांगनाओं के झेले गए दुखों से परेशान–कातर नहीं थीं। उन पर रोने–धोने के बजाय वह जीवन संग्राम से जूझते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को सशक्त बनाती आई थीं। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, 'तमाम दुखों को झेलते हुए भारतीय नारियां पूरी तरह शुद्ध, समर्पिता हैं और उनकी एकमात्र सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षा सीता होने की हैं।' इस तरह, उन्होंने पाया कि स्त्रियां दुश्वारियां झेलने के लिए अपने को जैसे हमेशा तैयार रखती थीं। कित्तूर की रानी चेन्नामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान समेत वे तमाम नारियां, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया; और चिपको आंदोलन में भागीदारी निभाने वाली महिला सहित आज के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों को अपने बड़े ध्येय के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है। इसलिए स्वामी जी नई भारतीय स्त्रियों के लिए बलात एक मॉडल गढ़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही उनकी अंतर्निहित आध्यात्मिक बल को फिर से पाने में मदद करेगी। अतः उन्हें जीवन में आदेश–निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें आजादी की आवश्यकता है और निश्चित है कि अगर उन्हें आजादी दी जाए तो वह उचित काम ही करेंगी।

स्वामी जी ने गुरु गंभीर स्वर में यह उद्घोषित किया था, 'पहले आप स्त्रियों को शिक्षित करें और फिर उन्हें उन पर छोड़ दें, तब वे स्वयं आपसे कहेंगी कि उनके लिए क्या–क्या सुधार आवश्यक है। उनके मामले में दखल देने वाले आप होते कौन हैं?' नारी स्वातंत्र्य के भारतीय नारियों को इस महान आध्यात्मिक संन्यासी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी परम्परा आज भी प्रवहमान है। ❑❑

स्वतंत्रता का असली अर्थ स्वदेशी ही : प्रो. भगवती प्रकाश

देश के विकास एवं उन्नति के लिए स्वदेशी की महती आवश्यकता है। स्वदेशी, केवल वस्तु उपयोग नहीं अपितु, प्रत्येक भारतीय में स्वदेश के भाव जागरण का नाम है। स्वदेशी से ही भारत की एकता, संप्रभुता कायम रह सकती है। वहीं, भारत के आर्थिक विकास की गाथा भी स्वदेशी से ही लिखी जा रही है। स्वदेशी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए स्व को पहचानना और देश प्रथम की भावना जागृत कर भारत की स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ स्वदेशी से ही निकलता है। उक्त विचार त्रिपुरा विश्ववद्यालय के एमबीबी सभागार में आयोजित स्वदेशी उद्यमिता मंथन कार्यक्रम में बोलते हुए स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने व्यक्त किये। प्रो. शर्मा ने कहा त्रिपुरा भारत का छोटा राज्य हो सकता है, किन्तु विश्व के कई देशों से बड़ा है और यहां के युवाओं की क्षमता असिमित है। यदि सभी युवा उद्यमिता की ओर अग्रसर हो जाएं तो त्रिपुरा भारत के आर्थिक उन्नयन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां के लोग 14 देवताओं के चतुर्दश रूप की पूजा करने वाले प्रकृति, संस्कृति एवं उन्नति के उपासक हैं। यहां रोजगार की असीमित संभावाएं हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस. एन. धींगड़ा ने कहा कि भारत को 1947 में आजादी उपनिवेशवाद से मिली, लेकिन अंग्रेजों ने जाते–जाते अपने तंत्र को अंग्रेजियत से इतना सरोबार कर दिया कि अंग्रेज चले गये लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। संविधान निर्माण से लेकर भारत के कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ताना–बाना आजादी देने से पूर्व ही बुन दिया गया था जिसे लंबे समय से भारत ढोता आ रहा है। यदि स्वतंत्रता का सही अर्थ निकालना है और भारत को विश्व में स्वतंत्रता के मापदंड से मुखर करना है तो हमारे पास स्वदेशी ही एक मात्र विकल्प है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. दीपक शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी उन्नति का रास्ता है। विश्वविद्यालय ने दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार सृजन–संसाधन केन्द्र के माध्यम से विगत वर्षों में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त राज्य के अन्य विद्यार्थियों हेतु भी रोजगार सृजन के विभिन्न आयामों पर कार्य किया है और यह निरंतर जारी रहेगा। केन्द्र मानसिकता परिवर्तन से लेकर उद्योग एवं अकादमिक सहभागिता के माध्यम से बैंबू, रैमी, पोटैटो फाइबर, कागज निर्माण एवं मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को कुशल प्रशिक्षण देकर पारंगत कर रहा है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय, राज्य में विद्यार्थियों मध्य जॉब सीकर की अपेक्षा जॉब प्रोवाइडर की मानसिकता की प्रेरणा का केन्द्र बनता जा रहा है। भारत के विकास में प्रत्येक युवा का अपना अहम स्थान है जिसके लिए शैक्षिक संस्थानों को ही नहीं, समाज को भी आगे आने की नितांत आवश्यकता है।

इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी एवं स्वदेशी के राष्ट्रीय पदाधिकारी अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने रियल प्लानेट का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार त्रिपुरा का एक युवा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हैंडिक्राफ्ट ऑउटलेट्स की श्रंखला का निर्माण कर करीब 1500 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है और 1200 करोड़ रु. से अधिक की कंपनी का निर्माण कर चुका है। ऐसा युवा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अन्नदाजी ने ऐसे अन्य कई सफल व्यक्तियों के सफलता संबंधी उदाहरण प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम कें बोलते हुए टेक्नो इंडिया, त्रिपुरा के कुलपति प्रो. रतन कुमार साहा ने कहा कि यहां युवा सह अवसर पाकर देशभर में अच्छा नाम कर रहे हैं। उन्होंने कई सफल युवाओं के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति (प्र.), प्रो. श्यामल दास ने अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा।

कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रो. शाओन राय चौधुरी, निदेशक, आईक्यूएस, त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. दीबाकर देब, प्राचार्य, टेक्नो इंडिया अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अगरतला ने दिया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय, टेक्नो इंडिया तथा स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. मुनीन्द्र मिश्र, उप कुलसचिव, त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने किया। कार्यक्रम में राज के 1200 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की तथा लाभान्वित हुए। ❑❑

भारत भर में भव्य स्वदेशी संकल्प दौड़

"जय स्वदेशी–जय–जय स्वदेशी" के उद्घोष के साथ भारतीय चित्ति के अद्भुत आलोक पुंज, चिर सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती 12 जनवरी से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष के सजग सिपाही सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी 2026 तक देश के सभी 45 प्रांतों के 564 जिलों में *स्वदेशी संकल्प दौड़* के 52635 कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें रिकॉर्ड 68,29,360 युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी मूल्यों के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में 12 दिवसीय स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच–स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा किया गया।

स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती (12 जनवरी 2026) जिसे वर्ष 1984 से ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर आयोजित कन्याकुमारी में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम ने हरी झंडी दिखाकर स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक की उपस्थिति में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने–अपने राज्यों में कार्यक्रम की अगुवाई की। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ राजीव, देवरिया से सांसद शशांकमणि त्रिपाठी, मुरादाबाद में रितेश गुप्ता के साथ–साथ जयपुर व्यापार संघ के महामंत्री सुरेश सैनी, नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंधी, जयपुर व्यापार मंडल के सुभाष गोयल आदि ने भी विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हुए बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के नेतृत्व में स्वामी जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी जागरूकता बढ़ाना और भारतीय उत्पादों को समर्थन देना,स्वस्थ जीवन शैली, अनुशासन और टीमवर्क की संस्कृति का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाना तथा नए भारत के निर्माण में

सक्रिय भूमिका के लिए विवेकानंद जी की शिक्षाओं से विद्यार्थियों में प्रेरणा जागृत करना था।

कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी अपनाओ, देश को अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाओ का आह्वान करते हुए स्वदेशी स्वरोजगार और नए भारत में युवाओं की भूमिका को लेकर प्रेरक संबोधन दिए गए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वदेशी भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विचार है। विवेकानंद जी ने कहा था कि 'जो राष्ट्र अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता'। स्वदेशी इस दिशा में खड़े होने का प्रभावी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी संकल्प दौड़ की जड़ में आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल का सम्मान, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति का भाव निहित है।

'विचारों में विवेकानंद कर्मों में स्वदेशी' और 'रन फार स्वदेशी रन फार भारत' का जयघोष कर विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए स्वदेशी, युवा शक्ति एवं आत्मनिर्भरता विषय पर प्रेरणादायी विचार विमर्श आयोजित हुए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश भक्ति गीत, भाषण प्रतियोगिता एवं लघु नाटिकाओं से सुसज्जित संस्कृतिक कार्यक्रम हुए। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर संवादात्मक विमर्श भी आयोजित किए गए। इस दौरान भारी संख्या विद्यार्थियों ने विशेष रूप से स्वदेशी संकल्प शपथ ली।

12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2026 तक पूरे भारतवर्ष में एक लाख से अधिक स्वदेशी संकल्प दौड़ और स्वदेशी संकल्प सभाओं का आयोजन हुआ। बारह दिवसीय आयोजनों में देश के पांच करोड़ से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर स्वदेशी संकल्प यात्राएं आयोजित की गई। इस दौरान स्वदेशी संकल्प दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को विशेष प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। ❑❑

स्वदेशी शोध संस्थान में मकर संक्रांति पर कार्यक्रम

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दिल्ली स्थित ज्ञान कुंज स्वदेशी शोध संस्थान में स्थित मां लक्ष्मी एवं भगवान गणेश के विग्रह की मुख्य यजमान श्री पूरन डाबर जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पर पूजनीय महामंडलेश्वर श्री कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज, अ.भा. संगठक माननीय श्री कश्मीरी लाल, अ.भा. सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन, सांसद बांसुरी स्वराज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री विपिन जोशी, जीएसटी कमिश्नर श्री राघवेंद्र पाल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री पंकज सिन्हा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री मनोज धनकर, अधिवक्ता परिषद के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर, विधायक श्री अनिल शर्मा, विधायक श्री जितेंद्र महाजन, राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल (भारत तिब्बत सहयोग मंच), स्वदेशी शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप चौहान, सेक्रेटरी सरबजीत कौर सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

जय स्वदेशीः जय–जय स्वदेशी

परेड ग्राउंड, देहरादून में दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तराखंड द्वारा नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के संयोजन में आयोजित 'स्वदेशी संकल्प दौड़' में व्यापारिक संगठनों, युवा उद्यमियों एवं समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्वर्णकार महासंघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री पंकज मैसोंन सहित अनेक प्रमुख व्यापारी नेता उपस्थित रहे। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने "गर्व से कहो – यह स्वदेशी है" एवं "जय स्वदेशी, जय–जय स्वदेशी" जैसे प्रेरणादायक नारों के माध्यम से स्वदेशी अपनाने का संदेश जन–जन तक पहुँचाया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील जे. सिंघी, स्वदेशी जागरण मंच संयोजक संजय कुमार, भाजयुमो प्रदेश मंत्री उत्कर्ष गुप्ता, भाजयुमो युवा महानगर अध्यक्ष कुलदीप पंत, युवा संरक्षक अर्चित डावर, उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, मुख्य संरक्षक सुशील अग्रवाल, संगठन सलाहकार संजय गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर फुलारा, उपाध्यक्ष हरीश विरमानी, महामंत्री पंकज डिढ़ान, लीगल एडवाइजर शिवा वर्मा, युवा अध्यक्ष मनन आनंद, युवा कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, युवा महामंत्री दिव्य सेठी, युवा उपाध्यक्ष मनीष फुलारा, युवा कोषाध्यक्ष रजत गुप्ता, युवा सचिव बॉबी कुमार सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी संकल्प दौड़

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वदेशी जागरण मंच एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। युवाओं को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डा. राजीव कुमार ने कहा कि रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता भी है, जिसे अपनाकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे, क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख कुलदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय सतानंद शर्मा ने आत्मनिर्भरता को स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का माध्यम बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ आयाम प्रमुख डा. एके अग्रवाल, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, कपिल नारंग, जिला सहसंयोजक नीरज सोलंकी, पारकर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य एसके नाथन आदि उपस्थित रहे।

2037 में विश्व गुरु बनेगा भारत : ढांडा

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य और स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने लिखित भाषण के पन्नों को बंद करते हुए कहा कि भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के दम पर 2037 तक विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा, आज पूरे विश्व में जिस तरह के हालात हैं और महाशक्तियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से एक होड़ मची हुई है। वहीं, भारत की 140 करोड़ आबादी पूरे विश्व को "विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो" का संदेश दे रही है। भारतीय संस्कृति की यही ताकत है जो उसे 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से 10 वर्ष पहले ही विश्व गुरु के मुकाम तक पहुंचा देगी।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह संयोग का विषय है कि देश के 1167 विवि में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन की शुरुआत सबसे पहले कुवि से हो रही है, जिसमें देशभर के लगभग 55 हजार महाविद्यालय सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का मूल मंत्र एकाग्रता है। और स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण

जीवन इसी विचार का प्रतीक है। उन्होंने सभी को स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दिलाया।

इस अवसर पर विवि के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा व कुलसचिव प्रो. वीरेन्द्र पाल सिंह सहित डा. ममता सचदेवा, डीन आफ कालेजिज प्रो. ब्रजेश साहनी, प्राक्टर प्रो. अनिल गुप्ता, मुख्य सुरक्षा अधिकारी डा. आनंद कुमार, प्रो. संजीव शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डा. अंकेश्वर प्रकाश, प्रो. परमेश कुमार व ललित कला विभाग के अध्यक्ष डा. गुरचरण सिंह मौजूद रहे।

स्वदेशी महोत्सव 2025 में स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति का संगम

पंचकूला सेक्टर–5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 लोगों के लिए स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, धर्म और स्वदेशी विचारधारा का एक सशक्त मंच बनकर उभरा। महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों की भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर विशेष तौर पर स्वदेशी जागरण मंच के अ.भा. संगठक श्री कश्मीरी लाल पहुंचे। आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ–साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना और भारतीय संस्कृति व संस्कारों से जोड़ना रहा। निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप में अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा रक्तचाप, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। सैकड़ों लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लोक नृत्य, देशभक्ति गीत और हरियाणवी संस्कृति की रंगारंग झलक देखने को मिली।

इस मौके पर श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि तुलसी का धार्मिक ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक महत्व भी अत्यंत बड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा और गति मिली है। स्वदेशी मेले के आयोजक रजनीश गर्ग ने बताया कि यह मेला केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, संस्कृति और पारंपरिक खेलों को एक मंच पर लाने का प्रयास है।

स्वदेशी मेला में हस्तशिल्पकारों का आमदनी के साथ मनोबल भी बढा

स्वदेशी मेला (सीतामढ़ी) के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नागपुर से स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अजय पतकी एवं पूर्व अखिल भारतीय महिला प्रमुख श्रीमति अमिता पतकी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह मा. अभय कुमार गर्ग, विभाग सह संघसंचालक मा. जय किशोर क्षेत्र संगठक स्वदेशी जागरण मंच श्री अजय कुमार जी, प्रांत संयोजक रमाशंकर हिंदवानी, डॉ प्रतिमा आनंद, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, सुरसंड के पूर्व मुख्य पार्षद राजू झा, समाजसेवी अभिषेक मिश्रा शिशु, अधिवक्ता परिषद की जिला संयोजक सीमा कुमारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अतिथियों का स्वागत मेला संयोजक श्रीमती संगीता झा ने किया। स्वदेशी मेला ने उन छोटे कारीगरों हस्तशिल्पियों को यह एहसास कराया कि वह छोटे नहीं है जब वह स्वदेशी मेला में आ जाते हैं और लोग उन्हें इतने बीच में देखते हैं तो वह बड़े हो जाते हैं और स्वदेशी मेला का यही कार्य है कि वह छोटे लोगों को बाजार देकर ब्रांड बनाएं। कार्यक्रम का संचालन मेला सचिव डॉ देवेश कुमार ने किया।

'स्वदेशी संकल्प यात्रा' का स्वागत

स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर निकाली जा रही 'स्वदेशी संकल्प यात्रा' गोरखपुर पहुंची। शहर में पहुंचने पर इस यात्रा का भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और अन्य व्यापारिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। टाउनहाल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन करते हुए व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया।

स्वदेशी जागरण मंच (गोरक्ष प्रांत) के संयोजक धीरज राय का स्वागत व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भोला प्रसाद अग्रहरी ने किया। इस दौरान क्षेत्र संयोजक अनुपम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। महानगर संयोजक सौरभ कुमार सिंह के नेतृत्व में यात्रा गोलघर से काली मंदिर चौराहा पहुंची, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विदेशी आर्थिक दबाव और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का सशक्त जवाब स्वदेशी अपनाकर ही दिया जा सकता है। व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और 'नेशन फर्स्ट' के संकल्प को व्यवहार में उतारें।

पेसिफिक विवि में स्वदेशी संकल्प रैली का आयोजन

पेसिफिक विश्वविद्यालय (उदयपुर) में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में स्वदेशी पर एक वार्ता एवं स्वदेशी संकल्प रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निम्बाराम (प्रांत प्रचारक) थे एवं विशिष्ठ अतिथि प्रो बी.पी.शर्मा (ग्रुप प्रेसिडेंट पाहेर यूनिवर्सिटी) एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो हेमंत कोठारी (वाइस चांसलर पाहेर यूनिवर्सिटी) ने की। इस अवसर पर डॉ हेमंत पंड्या, डॉ कपिलेश तिवारी, डॉ जितेन्द्र सिंह चुण्डावत सहित सभी संघटक महाविद्यालयों के डीन व डायरेक्टर्स उपस्थित रहे एवं सभी छात्र उपस्थित रहे। ❑❑

स्वदेशी संकल्प दौड़

सचित्र झलक

उत्तर काशी

उदयपुर

गोरखपुर

छत्तीसगढ़

झुंझुनू

देहरादून

नैनीताल

पैसिफिक विश्वविधालय

बागेश्वर

बिजनौर

इंफाल

मेरठ

रानीखेत

लखनऊ

सवाईमाधोपुर

स्वदेशी उद्यमिता मंथन, त्रिपुरा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जनवरी 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697 / 96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी संकल्प दौड़

सचित्र झलक

बागपत

भोपाल

मणिपुर

डिब्रूगढ़

दुर्ग

ग्रेटर नोएडा

हिसार

जगन्नाथपुरी

कालाहांडी

कोरापुट

कोटा

मुरादाबाद

नागालैंड

राउरकेला

सिलिगुड़ी

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

त्रिपुरा

अमरोहा

अरुणाचल प्रदेश

असम (उत्तर)

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती